

श्री क्षात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन (SKPF) एवं WINCOMPETE- संयुक्त टेस्ट सीरीज - 2026

समय: 2:00 घण्टे |

| अधिकतम अंक: 300

विषय: भारतीय संविधान -संवैधानिक विकास व सिद्धांत

टेस्ट संख्या: [14]

अभ्यर्थी का नाम: _____

अनुक्रमांक (Roll No.): _____

परीक्षा केंद्र _____

हस्ताक्षर अभ्यर्थी: _____

हस्ताक्षर वीक्षक: _____

परीक्षार्थियों के लिए निर्देश

1. इस प्रश्न-पुस्तिका में कुल 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के चार विकल्प (A, B, C, D, E) दिए गए हैं।
2. प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक निर्धारित हैं।
3. **नकारात्मक अंकन (Negative Marking):** प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा।
4. OMR उत्तर पत्रक में पाँच विकल्प (A, B, C, D, E) में एक का अंकन करना है। यदि आप किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते हैं, तो अनिवार्य रूप से विकल्प 'E' को अंकित करें।
5. यदि अभ्यर्थी किसी प्रश्न को हल नहीं करता है और विकल्प 'E' को भी अंकित नहीं करता है, तो उस प्रश्न के लिए भी 1/3 भाग (1 अंक) काटा जाएगा। (नवीनतम RPSC नियम)
6. कच्चे कार्य (Rough work) के लिए स्थान इस पुस्तिका के अंत में दिया गया है।
7. अपने रोल नम्बर और अन्य विवरण केवल निर्धारित स्थान पर ही लिखें।

Test 14 - भारतीय संविधान -संवैधानिक विकास व सिद्धांत

प्रश्न 1: भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रांतीय द्वैध शासन विन्यास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन I : अधिनियम के तहत प्रांतीय कार्यकारी परिषद के सदस्यों को हस्तांतरित विषयों का प्रभार सौंपा गया था, जो प्रांतीय विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों के प्रति विधिक रूप से उत्तरदायी थे।

कथन II : स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, चिकित्सा प्रशासन और कृषि जैसे लोक-कल्याणकारी विषयों को हस्तांतरित श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था।

कथन III : प्रांतीय गवर्नर को हस्तांतरित विषयों के संबंध में मंत्रियों द्वारा दी गई विधिक सलाह को विशेष परिस्थितियों में खारिज करने या अधिभावी (Override) करने का संप्रभु विवेकाधीन अधिकार प्राप्त था।

निम्न में से कौनसा /कौनसे कथन सत्य है -

- A) केवल कथन I और II
- B) केवल कथन II और III
- C) केवल कथन I और III
- D) केवल कथन II

प्रश्न 2: भारत शासन अधिनियम 1919 के बजटीय प्रणालियों और वित्तीय नियंत्रण के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथन और कारण पर विचार कीजिए:

कथन: भारत शासन अधिनियम 1919 के लागू होने के पश्चात केंद्रीय बजटीय अनुदान मांगों को प्रांतीय बजटीय संवीक्षा से वैधानिक रूप से पृथक् कर दिया गया।

कारण: मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड विन्यास के तहत प्रांतीय विधान परिषदों को अपने वित्तीय घाटे की पूर्ति के लिए बिना किसी केंद्रीय विनियामक अनुमोदन के स्वतंत्र रूप से विदेशी ऋण बाजार से पूंजी उगाहने की पूर्ण संप्रभुता दी गई थी।

- A) कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण, कथन की सही व्याख्या करता है
- B) कथन और कारण दोनों सत्य हैं परंतु कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं करता है

- C) कथन सत्य है परंतु कारण असत्य है
- D) कथन असत्य है परंतु कारण सत्य है

प्रश्न 3: भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत स्थापित द्विसदनीय केंद्रीय विधायिका की विनियामक शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों और निष्कर्षों का मूल्यांकन कीजिए:

कथन: 1919 के अधिनियम द्वारा निर्मित केंद्रीय विधानसभा (लोअर हाउस) में कुल सदस्यों की सांख्यिकी 145 निश्चित की गई थी, जिसमें निर्वाचित सदस्यों की संख्या 104 विन्यासित थी।

निष्कर्ष I : केंद्रीय विधायिका के भीतर निर्वाचित भारतीय सदस्यों को वायसराय की कार्यकारी परिषद के विरुद्ध पूर्ण विधायी संप्रभुता और अविश्वास प्रस्ताव पारित करने का विधिक अधिकार प्राप्त था।

निष्कर्ष II : गवर्नर-जनरल (वायसराय) के पास केंद्रीय विधायिका द्वारा अस्वीकृत या कटौती किए गए किसी भी बजटीय अनुदान को 'प्रमाणीकरण' (Certification) द्वारा स्वतः बहाल करने की असाधारण शक्ति अक्षुण्ण थी।

- A) केवल निष्कर्ष I सत्य है
- B) केवल निष्कर्ष II सत्य है
- C) निष्कर्ष I और II दोनों असत्य हैं
- D) केवल निष्कर्ष I और II दोनों सत्य हैं

प्रश्न 4: ब्रिटिश भारत के विभिन्न शासन अधिनियमों के विनियामक लक्षणों को उनके आधिकारिक मूलाधारों के साथ सुमेलित कीजिए:

सूची I :

- a) प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन (Dyarchy) का प्रवर्तन
- b) प्रांतीय स्वायत्तता (Provincial Autonomy) का विधिक क्रियान्वयन
- c) केंद्र के स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली का सांस्थानिक विन्यास
- d) गवर्नर-जनरल को अवशिष्ट शक्तियों (Residuary Powers) का संप्रभु हस्तांतरण

सूची II :

- 1. भारत शासन अधिनियम 1935 का केंद्रीय संस्तर

2. भारत शासन अधिनियम 1935 का सामान्य विन्यास
3. भारत शासन अधिनियम 1919 की प्रांतीय योजना
4. भारत शासन अधिनियम 1935 का संघीय विधायी प्रक्रम

- A) a-3, b-1, c-2, d-4
B) a-3, b-2, c-1, d-4
C) a-2, b-3, c-4, d-1
D) a-4, b-2, c-1, d-3

प्रश्न 5: भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत शक्तियों के त्रिविध आनुपातिक विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असंगत है?

- A) संघ सूची के अंतर्गत कुल 59 विषयों को समाहित किया गया था, जिसमें बाह्य मामले, नौसेना, वायुसेना और मुद्रा जैसे सामरिक महत्व के विषय विन्यासित थे।
B) प्रांतीय सूची के भीतर सांख्यिकीय रूप से 54 विषयों को स्थान दिया गया था, जिसमें प्रांतीय लोक व्यवस्था, न्याय प्रशासन, पुलिस और प्रांतीय कारागार सम्मिलित थे।
C) समवर्ती सूची के अंतर्गत विनियामक रूप से 42 विषयों को प्रख्यापित किया गया था, जिसमें दंड विधि, दंड प्रक्रिया, विवाह और नागरिक प्रक्रिया विलेख शामिल थे।
D) यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्रीय कानून और प्रांतीय कानून के मध्य विधिक टकराव उत्पन्न होता, तो गवर्नर-जनरल की पूर्व सहमति से निर्मित प्रांतीय कानून केंद्रीय कानून पर प्रभावी हो सकता था।

प्रश्न 6: नीचे दिए गए अकादमिक परिच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित एकल विश्लेषणात्मक प्रश्न का उत्तर दीजिए:

"भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत परिकल्पित 'अखिल भारतीय संघ' (All India Federation) ब्रिटिश भारत के प्रांतों, मुख्य आयुक्त के प्रांतों और उन देशी रियासतों के प्रशासनिक एकीकरण पर आधारित था जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित होने के विलेख पर हस्ताक्षर करने हेतु तैयार हों।"

उपरोक्त परिच्छेद के आलोक में, इस ऐतिहासिक संघीय योजना के कभी भी धरातल पर क्रियान्वित न हो पाने का प्राथमिक विनियामक कारण क्या था?

A) ब्रिटिश संसद ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीखे विरोध के कारण प्रादेशिक खंड को वैधानिक रूप से वापस ले लिया था।

B) देशी रियासतों के शासकों ने अपनी संप्रभुता के हास के भय से अनिवार्य 'एक्सेशन विलेख' (Instrument of Accession) पर हस्ताक्षर करने से पूर्ण इनकार कर दिया।

C) संघीय न्यायालय (Federal Court) ने रियासतों के राजाओं के विधिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर इस योजना पर पूर्ण विनियामक स्थगन लगा दिया था।

D) ब्रिटिश भारत के प्रांतों के गवर्नरों ने अपने प्रांतों की राजकोषीय स्वायत्तता के विखंडन के डर से इस संघ का तीक्ष्ण प्रशासनिक विरोध किया था।

प्रश्न 7: भारत शासन अधिनियम 1935 के सांस्थानिक मील के पथरों के अंतर्गत स्थापित 'संघीय न्यायालय' (Federal Court) की विधिक प्रकृति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है?

- A) यह न्यायालय भारत का सर्वोच्च और अंतिम अपील विलेख था, जिसके निर्णयों के विरुद्ध कहीं भी अपील दायर करना पूर्णतः वर्जित था।
B) इसके पास प्रांतों और संघीय सरकार के मध्य उत्पन्न होने वाले विधिक संवैधानिक विवादों के समाधान हेतु प्रारंभिक क्षेत्राधिकार निहित था।
C) इस न्यायालय की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग आयोग की विशिष्ट सिफारिशों के आधार पर कलकत्ता में की गई थी।
D) इसके मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की विधिक आयु सीमा आधुनिक उच्चतम न्यायालय के समान 65 वर्ष विन्यासित थी।

प्रश्न 8: भारत शासन अधिनियम 1919 की वैधानिक कमियों और प्रशासनिक विचलनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन I : केंद्रीय स्तर पर वायसराय की कार्यकारी परिषद के कुल छह सदस्यों में से तीन सदस्यों का भारतीय होना विधिक रूप से अनिवार्य विन्यासित किया गया था।

कथन II: अधिनियम के तहत सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का संकुचन करते हुए सिखों और भारतीय ईसाइयों को सामान्य मतदाता सूची में समाहित किया गया।

कथन III : अधिनियम के प्रवर्तन के नियमों के तहत मद्रास, बम्बई और संयुक्त प्रांत सहित सभी

प्रांतीय विधान परिषदों में महिलाओं को पुरुषों के समान बिना किसी प्रतिबंध के पूर्ण सार्वभौमिक मताधिकार प्राप्त हुआ।

निम्न में से **कौनसा / कौनसे कथन सत्य है -**

- A) केवल कथन I
- B) केवल कथन I और II
- C) केवल कथन II और III
- D) केवल कथन III

प्रश्न 9: भारत शासन अधिनियम 1935 के वित्तीय विन्यास और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की स्थापना के राजकोषीय कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथन और कारण पर विचार कीजिए:

कथन: भारत शासन अधिनियम 1935 के विनियामक ढांचे के तहत देश की मौद्रिक स्थिरता, साख नियंत्रण और मुद्रा संचलन के प्रबंधन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना को वैधानिक रूप से पुष्ट किया गया।

कारण: ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार भारत के वित्तीय संसाधनों पर से अपना विनियामक नियंत्रण पूरी तरह हटाकर इसे केंद्रीय विधायी मंत्रियों के पूर्ण बजटीय नियंत्रण के अधीन सौंपना चाहती थी।

- A) कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण, कथन की सही व्याख्या करता है
- B) कथन और कारण दोनों सत्य हैं परंतु कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं करता है
- C) कथन सत्य है परंतु कारण असत्य है
- D) कथन असत्य है परंतु कारण सत्य है

प्रश्न 10: 1919 के अधिनियम के तहत 'मेस्टन योजना' (Meston Scheme) द्वारा जनित वित्तीय गतिकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों और निष्कर्षों का मूल्यांकन कीजिए:

कथन: वर्ष 1919 के वित्तीय सुधारों के अंतर्गत गठित मेस्टन समिति ने केंद्र और प्रांतों के बीच राजस्व स्रोतों के विभाजन के बाद प्रांतीय सरकारों पर केंद्रीय घाटे की पूर्ति का वित्तीय दायित्व आरोपित किया।

निष्कर्ष I : इस योजना के दमनकारी बजटीय प्रावधानों के कारण प्रांतीय सरकारों को अपने हस्तांतरित लोक-कल्याणकारी विषयों को लागू करने हेतु पर्याप्त बजटीय संसाधन प्राप्त हुए।

निष्कर्ष II : 'प्रांतीय अंशदान' (Provincial Contribution) की इस विवशता ने प्रांतों की

वास्तविक राजकोषीय स्वायत्तता को गंभीर रूप से पंगु बना दिया, जिसका प्रांतों ने कड़ा विरोध किया।

- A) केवल निष्कर्ष I सत्य है
- B) केवल निष्कर्ष II सत्य है
- C) निष्कर्ष I और II दोनों असत्य हैं
- D) निष्कर्ष I और II दोनों सत्य हैं

प्रश्न 11: बीसवीं शताब्दी के औपनिवेशिक विधायी विलेखों के अंतर्गत हुए महत्वपूर्ण प्रशासनिक परिवर्तनों को उनके वास्तविक क्रियान्वयन के वर्षों के साथ सुमेलित कीजिए:

सूची I :

- a) भारत से बर्मा (म्यांमार) का विधिक प्रादेशिक विच्छेद
- b) केंद्रीय लोक सेवा आयोग (CPSC) की आधिकारिक स्थापना
- c) प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का व्यावहारिक उन्मूलन
- d) मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों के तहत प्रांतीय द्वैध शासन का वास्तविक प्रारंभ

सूची II :

- 1. वर्ष 1921
- 2. वर्ष 1926
- 3. वर्ष 1937
- 4. वर्ष 1939

- A) a-3, b-2, c-1, d-4
- B) a-3, b-2, c-3, d-1
- C) a-2, b-3, c-1, d-4
- D) a-1, b-2, c-3, d-4

प्रश्न 12: भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 'प्रांतीय स्वायत्तता' (Provincial Autonomy) के प्रशासनिक लक्षणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन **असंगत** है?

- A) प्रांतों को अब केंद्र के विनियामक नियंत्रण से मुक्त कर अपने स्वयं के परिभाषित विधिक दायरे में संप्रभुता से शासन संचालित करने वाली पृथक विधिक इकाइयाँ माना गया।
- B) प्रांतीय गवर्नर अब पूरी तरह से प्रांतीय मंत्रियों की विधिक सलाह पर कार्य करने हेतु बाध्य था और उसके पास कोई विवेकाधीन या वीटो अधिकार शेष नहीं थे।
- C) प्रांतीय कार्यपालिका का गठन प्रांतीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों से होता था, जिन्हें विधायिका में अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता था।

D) इस अधिनियम ने बम्बई, बंगाल, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम सहित छह प्रांतों में द्विसदनीय (Bi-cameral) विधानमंडलों का विन्यास किया।

प्रश्न 13: नीचे दिए गए ऐतिहासिक परिच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित एकल विश्लेषणात्मक प्रश्न का उत्तर दीजिए:

"1919 के अधिनियम के तहत प्रख्यापित मताधिकार अत्यधिक संकीर्ण था, जो केवल संपत्ति के स्वामित्व, भू-राजस्व के भुगतान और उच्च शैक्षणिक योग्यताओं पर आधारित था। इसके कारण ब्रिटिश भारत की विशाल जनसांख्यिकी का एक बहुत छोटा भाग ही चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा बन सका।"

उपरोक्त परिच्छेद के सांख्यिकीय विन्यास के आलोक में, 1919 के अधिनियम द्वारा भारत की कुल जनसांख्यिकी के कितने प्रतिशत भाग को विधिक रूप से मताधिकार प्राप्त हुआ था?

- A) लगभग 3 प्रतिशत
- B) लगभग 10 प्रतिशत
- C) लगभग 25 प्रतिशत
- D) लगभग 50 प्रतिशत

प्रश्न 14: भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत लोक सेवा आयोगों के बहु-स्तरीय सांस्थानिक ढांचे के विन्यास के संदर्भ में कौन सा एकल विकल्प सत्य प्रतिरूप को प्रदर्शित करता है?

- A) अधिनियम ने केवल केंद्र के लिए एक संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया, जबकि प्रांतों को अपनी स्वयं की भर्ती एजेंसियां बनाने की विधायी शक्ति नहीं दी।
- B) दो या दो से अधिक प्रांतों की साझा प्रशासनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक 'संयुक्त लोक सेवा आयोग' (Joint Public Service Commission) के गठन का वैधानिक मार्ग प्रशस्त किया गया।
- C) संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की विधिक नियुक्ति संबंधित राज्यों के गवर्नरों की एक संयुक्त विनियामक समिति द्वारा की जाती थी।
- D) प्रांतीय लोक सेवा आयोग के सदस्यों को उनके पद से हटाने की संप्रभु विधिक शक्ति केवल प्रांतीय मुख्यमंत्रियों के पास सुरक्षित रखी गई थी।

प्रश्न 15: भारत शासन अधिनियम 1919 के विधायी नियंत्रण और बजटीय विन्यास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन I : केंद्रीय बजट का लगभग 65 प्रतिशत भाग गैर-मतदान योग्य (Non-votable) श्रेणी के अंतर्गत संचित निधि पर भारित रखा गया था, जिस पर विधायी बहस तो हो सकती थी परंतु मतदान वर्जित था।

कथन II: केंद्रीय विधानमंडल के दोनों सदनों के मध्य किसी विधेयक पर गतिरोध उत्पन्न होने की स्थिति में संयुक्त बैठक (Joint Sitting) बुलाने का कोई वैधानिक प्रावधान 1919 के अधिनियम में नहीं था।

कथन III : भारतीय संप्रभुता के विन्यास के तहत भारत सचिव (Secretary of State for India) के वेतन और भत्तों को ब्रिटिश राजस्व के स्थान पर भारतीय राजस्व पर भारित बनाए रखा गया। निम्न में से **कौनसा /कौनसे कथन सत्य है -**

- A) केवल कथन II
- B) केवल कथन I
- C) केवल कथन I और III
- D) केवल कथन III

प्रश्न 16: भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रादेशिक पुनर्गठन और प्रशासनिक भूगोल के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथन और कारण पर विचार कीजिए:

कथन: भारत शासन अधिनियम 1935 के विधिक प्रावधानों के प्रवर्तन के फलस्वरूप भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी और पूर्वी सीमाओं पर दो नए प्रांतों, उड़ीसा और सिंध का निर्माण किया गया।

कारण: इन दोनों नए प्रांतों का गठन विशुद्ध रूप से प्रशासनिक सुगमता के स्थान पर भाषाई और सांप्रदायिक जनसांख्यिकी के संतुलन को विधिक रूप से सुदृढ़ करने के उद्देश्य से किया गया था।

- A) कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण, कथन की सही व्याख्या करता है
- B) कथन और कारण दोनों सत्य हैं परंतु कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं करता है
- C) कथन सत्य है परंतु कारण असत्य है
- D) कथन असत्य है परंतु कारण सत्य है

प्रश्न 17: 1935 के अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली के विनियामक विन्यास के संबंध में

निम्नलिखित कथनों और निष्कर्षों का मूल्यांकन कीजिए:

कथन: भारत शासन अधिनियम 1935 ने प्रांतों से द्वैध शासन को समाप्त कर उसे केंद्र के स्तर पर विस्थापित किया, जिसके तहत संघीय विषयों को आरक्षित (Reserved) और हस्तांतरित (Transferred) श्रेणियों में विभाजित किया गया।

निष्कर्ष I : रक्षा, वैदेशिक मामले, जनजातीय क्षेत्र और धार्मिक मामले जैसे देश के सर्वोच्च सामरिक महत्व के विषयों को भारतीय मंत्रियों के विनियामक नियंत्रण के अधीन 'हस्तांतरित' श्रेणी में रखा गया था।

निष्कर्ष II : आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर-जनरल अपनी परिषद (जिसमें अधिकतम तीन सदस्य हो सकते थे) की सहायता से करता था, जिनकी विधायी जवाबदेही केंद्रीय विधायिका के प्रति पूर्णतः शून्य थी।

- A) केवल निष्कर्ष I सत्य है
- B) केवल निष्कर्ष II सत्य है
- C) निष्कर्ष I और II दोनों असत्य हैं
- D) निष्कर्ष I और II दोनों सत्य हैं

प्रश्न 18: आधुनिक भारतीय संवैधानिक कड़ियों और औपनिवेशिक विलेखों के विनियामक स्रोतों को उनके विनिर्दिष्ट प्रावधानों के साथ सुमेलित कीजिए:

सूची I :

- a) वर्तमान भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के शक्तियों के विभाजन का मूल विन्यास
- b) केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संतुलन हेतु उत्तरदायी संस्थान का ऐतिहासिक मूलधार
- c) वर्तमान न्यायिक पिरामिड के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार और अपीलीय कड़ियों का ऐतिहासिक संस्तर
- d) आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार की विधायी सर्वोच्चता के प्रावधानों का विलेख

सूची II :

1. भारत शासन अधिनियम 1935 का संघीय न्यायालय संस्तर
2. भारत शासन अधिनियम 1935 की त्रिविध आनुपातिक विधायी सूचियाँ
3. भारत शासन अधिनियम 1935 का रिजर्व बैंक और ओटो नीमेयर वित्तीय विन्यास
4. भारत शासन अधिनियम 1935 की धारा 102 का संकटकालीन विधायी प्रक्रम

- A) a-2, b-3, c-4, d-1
- B) a-2, b-3, c-1, d-4
- C) a-3, b-2, c-1, d-4
- D) a-1, b-2, c-3, d-4

प्रश्न 19: भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा निर्मित 'राज्य परिषद' (Council of State) के सांख्यिकीय विन्यास और विधायी स्वरूप के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है?

- A) यह केंद्रीय विधायिका का उच्च सदन (Upper House) था, जिसका कार्यकाल विनियामक रूप से 5 वर्ष निश्चित किया गया था।
- B) इस सदन की कुल सदस्य संख्या 60 विन्यासित थी, जिसमें से सांख्यिकीय रूप से 34 सदस्यों का निर्वाचित होना अनिवार्य था।
- C) इस उच्च सदन के भीतर महिलाओं को सदस्यता प्राप्त करने और अपने मताधिकार का प्रयोग करने का विधिक अधिकार पूर्ण रूप से प्रदान किया गया था।
- D) इसके निर्वाचित सदस्यों का चयन अत्यंत सीमित चुनावी मेखला द्वारा किया जाता था, जिसमें मुख्य रूप से बड़े जमींदार, उद्योगपति और विशिष्ट उपाधि धारक ही पात्र थे।

प्रश्न 20: भारत शासन अधिनियम 1935 की वैधानिक सीमाओं और संप्रभुता के विन्यास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता औपनिवेशिक नियंत्रण को अक्षुण्ण बनाए रखने का अकादमिक प्रमाण प्रस्तुत करती है?

- A) अधिनियम ने ब्रिटिश संसद की वैधानिक सर्वोच्चता को बनाए रखा और भारतीय विधानमंडलों को इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के संशोधन का विधिक अधिकार नहीं दिया।
- B) इसने गवर्नर-जनरल को प्रांतीय और केंद्रीय दोनों स्तरों पर चुनी हुई सरकारों के किसी भी विलेख को बिना किसी विधिक कारण के सीधे निरस्त करने की निरंकुश शक्ति प्रदान की।
- C) अधिनियम ने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को पूरी तरह समाप्त कर उसके स्थान पर संयुक्त निर्वाचन प्रणाली को वैधानिक रूप से विस्थापित कर दिया था।
- D) इसने भारत सचिव (Secretary of State for India) के पद को पूरी तरह समाप्त कर उसकी सभी शक्तियों को सीधे भारतीय प्रधानमंत्री को हस्तांतरित कर दिया था।

प्रश्न 21: वर्ष 1919 और 1935 के अधिनियमों की बजटीय प्रणालियों तथा सांख्यिकीय विचलनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन I : भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत प्रख्यापित केंद्रीय व्यवस्थापिका में राज्य परिषद का सामान्य विधायी कार्यकाल सांख्यिकीय रूप से 3 वर्ष निश्चित था।

कथन II: भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय विधानसभा में देशी रियासतों के शासकों के नामांकन हेतु आनुपातिक रूप से 125 सीटें आरक्षित थीं।

कथन III : वर्ष 1935 के अधिनियम द्वारा प्रख्यापित प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत प्रांतीय स्तर पर कर संरचना के निर्धारण हेतु मेस्टन योजना के दमनकारी प्रांतीय अंशदान को विधिक रूप से अक्षुण्ण रखा गया था।
निम्न में से कौनसा /कौनसे कथन सत्य है -

- A) केवल कथन II
- B) केवल कथन I और II
- C) केवल कथन III
- D) केवल कथन II और III

प्रश्न 22: अगस्त प्रस्ताव (1940) तथा क्रिप्स मिशन (1942) के विनियामक प्रावधानों और उनके दूरगामी राजनीतिक निहितार्थों के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथन और कारण पर विचार कीजिए:

कथन: मार्च 1942 में प्रख्यापित क्रिप्स प्रस्तावों को महात्मा गांधी ने 'उत्तर-तिथीय चेक' (Post-dated Cheque) की विधिक वैधानिक संज्ञा दी थी।

कारण: क्रिप्स मिशन ने युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद भारत को पूर्ण संप्रभुता प्रदान करते हुए ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की वैधानिक स्वतंत्रता देने से पूर्ण इनकार कर दिया था।

- A) कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण, कथन की सही व्याख्या करता है
- B) कथन और कारण दोनों सत्य हैं परंतु कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं करता है
- C) कथन सत्य है परंतु कारण असत्य है
- D) कथन असत्य है परंतु कारण सत्य है

प्रश्न 23: कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत प्रांतों के अनिवार्य समूहीकरण (Grouping) और प्रादेशिक विन्यास के संबंध में निम्नलिखित कथनों और निष्कर्षों का मूल्यांकन कीजिए:

कथन: कैबिनेट मिशन 1946 ने भारत के लिए एक शिथिल केंद्रीकृत संघीय ढांचे का प्रारूप प्रस्तुत किया, जिसके तहत प्रांतों को तीन विशिष्ट समूहों में विधिक रूप से विभाजित किया गया था।

निष्कर्ष I : समूह 'B' के अंतर्गत उत्तर-पश्चिम मुस्लिम बहुल प्रांतों जैसे पंजाब, उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत और सिंध को प्रशासनिक रूप से विन्यासित किया गया था।

निष्कर्ष II : मिशन के विनिर्देशों के अनुसार असम और प्रांतों की ऐतिहासिक मेखलाओं को हिंदू बहुल संभाग के रूप में समूह 'A' के अंतर्गत विधिक रूप से वर्गीकृत किया गया था।

- A) केवल निष्कर्ष I सत्य है
- B) केवल निष्कर्ष II सत्य है
- C) निष्कर्ष I और II दोनों असत्य हैं
- D) निष्कर्ष I और II दोनों सत्य हैं

प्रश्न 24: भारत के संवैधानिक इतिहास से संबद्ध विभिन्न मिशनों, योजनाओं और उनके आधिकारिक प्रस्तावों को सुमेलित कीजिए:

सूची I :

- a) वायसराय की कार्यकारी परिषद में सवर्ण हिंदुओं और मुस्लिमों को पूर्ण सांख्यिकीय समानता देने की योजना
- b) प्रांतों को संघ से अलग रहने और पृथक विलेख बनाने का अनन्य विधिक अधिकार देने का प्रस्ताव
- c) अल्पसंख्यकों की स्पष्ट विधिक असहमति पर किसी भी शासन प्रणाली को सत्ता हस्तांतरण न करने का औपनिवेशिक वादा
- d) शिथिल केंद्रीकृत त्रि-स्तरीय संघ और 389 सदस्यीय अप्रत्यक्ष निर्वाचित संविधान सभा का ब्लूप्रिंट

सूची II :

- 1. सर स्टैफोर्ड क्रिप्स प्रस्ताव 1942
- 2. लॉर्ड पैथिक-लॉरेंस कैबिनेट मिशन योजना 1946
- 3. लॉर्ड लिनलिथगो अगस्त प्रस्ताव 1940

4. लॉर्ड वेवेल योजना 1945

- A) a-4, b-1, c-2, d-3
- B) a-4, b-1, c-3, d-2
- C) a-1, b-4, c-3, d-2
- D) a-4, b-2, c-3, d-1

प्रश्न 25: संविधान सभा के गठन की प्रारंभिक सांख्यिकी और जुलाई-अगस्त 1946 के दलीय चुनावी परिणामों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असंगत है?

- A) कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार, संविधान सभा की कुल प्रारंभिक सदस्य संख्या 389 निश्चित की गई थी, जिसमें से 93 प्रतिनिधि देशी रियासतों के थे।
- B) जुलाई-अगस्त 1946 में संपन्न प्रांतों की 296 सीटों के चुनाव में डॉ. बी. आर. अंबेडकर की पार्टी शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन ने 5 सीटों पर विधिक विजय प्राप्त की।
- C) लघु दलों और स्वतंत्र उम्मीदवारों के विन्यास के अंतर्गत सामान्य चुनावों में कुल 8 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने सफलता दर्ज की थी।
- D) चुनावी परिणामों के सांख्यिकीय विश्लेषण के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीटें तथा मुस्लिम लीग को कुल 73 सीटें प्राप्त हुई थीं।

प्रश्न 26: नीचे दिए गए ऐतिहासिक परिच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित एकल विश्लेषणात्मक प्रश्न का उत्तर दीजिए:

"संविधान सभा के भीतर शक्तियों का निर्धारण और जटिल विलेखों का निर्माण केवल उग्र दंडात्मक मतदान द्वारा नहीं होता था। सभा ने 'आम सहमति' (Consensus) और 'समायोजन' (Accommodation) के सिद्धांतों के प्रक्रियात्मक सत्य को सर्वोपरि विस्थापित किया था, जिसके कारण प्रत्येक खंड पर विस्तृत विमर्श किया जाता था।"

उपरोक्त परिच्छेद के आलोक में, प्रख्यात ब्रिटिश संविधान विशेषज्ञ ग्रैनविले ऑस्टिन ने अपनी किस प्रसिद्ध पुस्तक में संविधान सभा के दलीय संकेंद्रीकरण पर टिप्पणी करते हुए लिखा था कि 'सभा ही कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था'?

A) द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन: कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन

- B) वर्किंग ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन: ए हिस्ट्री ऑफ द इंडियन एक्सपीरियंस
- C) द इंडियन ट्रिनिटी: पार्लियामेंट, कैबिनेट एंड जुडिशियरी
- D) कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इन इंडिया: ए स्ट्रक्चरल एनालिसिस

प्रश्न 27: संविधान सभा की विभिन्न कार्यसमितियों, प्रारूप समिति (Drafting Committee) के विनियामक अधिकारों तथा नेतृत्व पद आर्डर के संदर्भ में कौन सा वैधानिक प्रतिरूप सत्य है?

- A) मौलिक अधिकार उप-समिति के प्रशासनिक प्रमुख विधिक रूप से एच. सी. मुखर्जी विनिर्दिष्ट किए गए थे।
- B) प्रारूप समिति के भीतर सैनी मोहम्मद सादुल्ला एकमात्र ऐसे सदस्य थे जो विशुद्ध रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दलीय टिकट पर निर्वाचित थे।
- C) संविधान सभा के कार्यों (विधायी संसद भूमिका) से संबद्ध विशेष समिति के विधिक अध्यक्ष का प्रभार जी. वी. मावलंकर को सौंपा गया था।
- D) तदर्थ राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष पद आर्डर का दायित्व सर्वसम्मति से आचार्य जे. बी. कृपलानी को सौंपा गया था।

प्रश्न 28: वर्ष 1919 और 1935 के अधिनियमों की प्रशासनिक गतिकी और प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के तुलनात्मक विश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन I : भारत शासन अधिनियम 1919 पूर्णतः एक एकात्मक शासन प्रणाली का विन्यास था, जिसमें प्रांतों को केंद्र से स्वतंत्र कोई विधिक अस्तित्व प्राप्त नहीं था।

कथन II: भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा प्रख्यापित 'अखिल भारतीय संघ' के विन्यास के अंतर्गत 11 ब्रिटिश प्रांतों का सम्मिलित होना पूरी तरह स्वैच्छिक रखा गया था।

कथन III : वर्ष 1935 के अधिनियम की धारा 104 के विधिक प्रावधानों के तहत अवशिष्ट शक्तियों (Residuary Powers) को पूरी तरह गवर्नर-जनरल के व्यक्तिगत विवेक के अधीन आरक्षित किया गया था।

निम्न में से कौनसा /कौनसे कथन सत्य है -

- A) केवल कथन I और II
- B) केवल कथन I और III
- C) केवल कथन II और III

D) केवल कथन III

प्रश्न 29: अंतरिम सरकार (1946) के गठन, सांस्थानिक विभागवार विन्यास और कार्यपालिका के भीतर उपजे प्रशासनिक गतिरोधों के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथन और कारण पर विचार कीजिए:

कथन: 2 सितंबर 1946 को गठित भारत की पहली आधिकारिक अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि लियाकट अली खान को 'वित्त विभाग' का विधिक प्रभार सौंपा गया था।

कारण: लॉर्ड वेवेल की कार्यकारी परिषद के भीतर वित्त विभाग के विनियामक कपाट पर नियंत्रण स्थापित करके मुस्लिम लीग कांग्रेस कमान के प्रत्येक नीतिगत और लोक-कल्याणकारी निर्णय को राजकोषीय संवीक्षा द्वारा बाधित करना चाहती थी।

- A) कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण, कथन की सही व्याख्या करता है
B) कथन और कारण दोनों सत्य हैं परंतु कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं करता है
C) कथन सत्य है परंतु कारण असत्य है
D) कथन असत्य है परंतु कारण सत्य है

प्रश्न 30: विभाजन विलेख (3 जून 1947) के प्रभाव से जनित सांख्यिकीय पुनर्गठन और प्रादेशिक विस्थापनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों और निष्कर्षों का मूल्यांकन कीजिए:

कथन: 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना के वैधानिक प्रवर्तन के पश्चात पाकिस्तान के क्षेत्राधिकार में जाने वाले भूखंडों के अलग होने से संविधान सभा की सदस्य संख्या में भारी हास दर्ज हुआ।

निष्कर्ष I : प्रादेशिक विभाजन के उपरांत 31 दिसंबर 1947 को पुनर्गठित भारतीय संविधान सभा में देशी रियासतों के मनोनीत प्रतिनिधियों की कुल सांख्यिकीय संख्या 93 से घटकर 70 रह गई।

निष्कर्ष II : पुनर्गठित प्रांतीय सीटों के अद्यतन सांख्यिकीय विन्यास के अंतर्गत सर्वोच्च विधायी प्रतिनिधित्व बम्बई प्रेसिडेंसी को कुल 49 सीटों के साथ प्राप्त हुआ था।

A) केवल निष्कर्ष I याद सत्य है

- B) केवल निष्कर्ष II याद सत्य है
C) निष्कर्ष I और II दोनों असत्य हैं
D) निष्कर्ष I और II दोनों सत्य हैं

प्रश्न 31: संविधान सभा की प्रमुख समितियों के वास्तविक गठन की ऐतिहासिक तिथियों तथा उनके विनियामक विलेखों को सुमेलित कीजिए:

सूची I :

- a) पंडित नेहरू द्वारा संविधान सभा के पटल पर ऐतिहासिक 'उद्देश्य प्रस्ताव' (Objective Resolution) का विधिक प्रस्तुतीकरण
b) संविधान सभा द्वारा संपूर्ण उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से आधिकारिक रूप से पारित और स्वीकार करने की तिथि
c) संविधान सभा द्वारा एक विशेष विधायी संकल्प पारित करके 'प्रारूप समिति' (Drafting Committee) का वैधानिक गठन
d) डॉ. भीमराव अंबेडकर को सर्वसम्मति से प्रारूप समिति का विधिक अध्यक्ष चुने जाने की तिथि कूट

सूची II :

1. 22 जनवरी 1947
2. 30 अगस्त 1947
3. 13 दिसंबर 1946
4. 29 अगस्त 1947

- A) a-3, b-1, c-2, d-4
B) a-3, b-1, c-4, d-2
C) a-1, b-3, c-4, d-2
D) a-3, b-4, c-1, d-2

प्रश्न 32: प्रारूप समिति (Drafting Committee) के सदस्यवार विन्यास, आंतरिक सांख्यिकी तथा अस्वस्थता व आकस्मिक विस्थापन के नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असंगत है?

- A) प्रारूप समिति में शामिल अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर मद्रास प्रांत के पूर्व एडवोकेट जनरल और प्रख्यात न्यायविद थे।
B) एन. माधव राव को प्रारूप समिति के मूल सदस्य बी. एल. मित्र द्वारा स्वास्थ्य कारणों से दिए गए विधिक त्यागपत्र के स्थान पर नियुक्त किया गया था।
C) वर्ष 1948 में प्रारूप समिति के मूल सदस्य डी. पी. खेतान की आकस्मिक मृत्यु हो जाने के कारण

सांख्यिकीय रिक्तता को भरने हेतु एन. गोपालस्वामी आयरंगर को शामिल किया गया।
D) डॉ. के. एम. मुंशी (कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी) प्रारूप समिति के भीतर एकमात्र ऐसे विशिष्ट सदस्य थे जो विशुद्ध रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मूल दलीय टिकट पर निर्वाचित थे।

प्रश्न 33: नीचे दिए गए ऐतिहासिक परिच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित एकल विश्लेषणात्मक प्रश्न का उत्तर दीजिए:

"3 जून 1947 की विभाजन योजना के प्रख्यापन के बाद भारत के भू-राजनीतिक नक्शे पर 'बाल्कनाइजेशन' का गंभीर संकट उत्पन्न हो गया था। त्रावणकोर और भोपाल जैसी बड़ी रियासतों के शासकों ने भारतीय संघ में शामिल होने से साफ मना कर दिया और अपनी पृथक संप्रभुता के विलेख तैयार करने लगे थे।"

उपरोक्त परिच्छेद में वर्णित देशी रियासतों के विद्रोही विन्यास के मध्य, 28 अप्रैल 1947 को संविधान सभा के तीसरे सत्र के दौरान सर्वप्रथम कितनी देशी रियासतों के मनोनीत प्रतिनिधियों ने सभा में अपनी वैधानिक प्रविष्टि दर्ज की थी?

- A) छह देशी रियासतों ने
- B) दस देशी रियासतों ने
- C) पंद्रह देशी रियासतों ने
- D) इक्कीस देशी रियासतों ने

प्रश्न 34: भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा जनित विधिक गतिकी और संविधान सभा की दोहरी विधायी भूमिका (Dual Role) के संदर्भ में कौन सा प्रशासनिक प्रतिरूप सत्य है?

- A) जब सभा देश के लिए सामान्य कानूनों का निर्माण करने हेतु अंतरिम संसद के रूप में बैठती थी, तो इसकी विधिक अध्यक्षता डॉ. राजेंद्र प्रसाद द्वारा की जाती थी।
- B) जब सभा स्वतंत्र भारत के भावी संविधान के निर्माण हेतु बैठती थी, तो इसकी अध्यक्षता का संप्रभु प्रभार जी. वी. मावलंकर वहन करते थे।
- C) संविधान सभा की यह दोहरी विधायी भूमिका और अंतरिम संसद के रूप में कार्य करने का प्रक्रम 26 जनवरी 1950 तक निरंतर गतिक बना रहा था।
- D) जब सभा अंतरिम व्यवस्थापिका के रूप में बैठती थी, तो उसकी अध्यक्षता करने वाले जी. वी.

मावलंकर स्वतंत्र भारत की प्रथम विधायी संसद के पहले स्पीकर बने।

प्रश्न 35: वर्ष 1919 और 1935 के अधिनियमों की सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणालियों तथा मताधिकार विस्तार चक्र के तुलनात्मक विश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन I : भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा पृथक निर्वाचन मंडल के वैधानिक कपाट को खोलकर इसमें सिख, भारतीय ईसाई, आंग्ल-भारतीय तथा यूरोपीय नागरिकों को शामिल किया गया।

कथन II: भारत शासन अधिनियम 1935 ने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को पूरी तरह समाप्त कर उसके स्थान पर संयुक्त निर्वाचन और वयस्क मताधिकार को विस्थापित किया।

कथन III : वर्ष 1919 के अधिनियम के तहत मताधिकार संकीर्ण था जिससे 3% जनसांख्यिकी मतदाता बनी, जबकि 1935 के अधिनियम में यह आयतन बढ़कर कुल जनसंख्या का लगभग 10% हो गया।

निम्न में से कौनसा /कौनसे कथन सत्य है -

- A) केवल कथन I
- B) केवल कथन II
- C) केवल कथन I और III
- D) केवल कथन II और III

प्रश्न 36: क्रिप्स मिशन (1942) की विफलता के अंतर्निहित विनियामक कारणों और समकालीन राष्ट्रवादी प्रतिक्रियाओं के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथन और कारण पर विचार कीजिए:

कथन: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों ने मार्च 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स द्वारा प्रस्तुत विधिक प्रस्तावों को पूर्णतः खारिज कर दिया था।

कारण: क्रिप्स प्रस्तावों में निहित 'नॉन-एक्सेशन क्लॉज' (Non-accession Clause) ने प्रांतों को भारतीय संघ से अलग रहने और पृथक विलेख बनाने का वैधानिक अधिकार देकर परोक्ष रूप से भारत के भौगोलिक विखंडन का बीज बोया था।

- A) कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण, कथन की सही व्याख्या करता है

- B) कथन और कारण दोनों सत्य हैं परंतु कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं करता है
C) कथन सत्य है परंतु कारण असत्य है
D) कथन असत्य है परंतु कारण सत्य है

प्रश्न 37: संविधान सभा के भीतर सामाजिक और जनसांख्यिकीय प्रतिनिधित्व के आनुपातिक विन्यास के संबंध में निम्नलिखित कथनों और निष्कर्षों का मूल्यांकन कीजिए:

कथन: यद्यपि संविधान सभा प्रत्यक्ष वयस्क मताधिकार द्वारा निर्वाचित नहीं थी, फिर भी इसके अप्रत्यक्ष चुनाव प्रतिरूप के कारण इसमें समकालीन भारत के समस्त सामाजिक और लैंगिक समूहों को प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ।

निष्कर्ष I : भारतीय संविधान सभा के प्रारंभिक संस्तर में महिला जनसांख्यिकी का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने हेतु कुल 15 महिला सदस्य शामिल थीं।

निष्कर्ष II : सभा के भीतर अपवंचित वर्गों के विधिक अधिकारों के संरक्षण हेतु कुल 33 सदस्य अनुसूचित जाति (SC) के तथा 26 सदस्य अनुसूचित जनजाति (ST) के विधिक रूप से शामिल थे।

- A) केवल निष्कर्ष I सत्य है
B) केवल निष्कर्ष II सत्य है
C) निष्कर्ष I और II दोनों असत्य हैं
D) निष्कर्ष I और II दोनों सत्य हैं

प्रश्न 38: संविधान सभा की कार्यप्रणाली के अंतिम चरणों के दौरान संपादित किए गए विशिष्ट वैधानिक कार्यों को उनकी आधिकारिक ऐतिहासिक तिथियों के साथ सुमेलित कीजिए:

सूची I :

- a) संविधान सभा द्वारा तिरंगे को भारत के आधिकारिक 'राष्ट्रीय ध्वज' के रूप में विधिक संस्तुति प्रदान करने की तिथि
b) राष्ट्रमंडल (Commonwealth) में स्वतंत्र भारत की सदस्यता का संविधान सभा द्वारा विधिक सत्यापन (Ratification) करने का वर्ष-माह कूट
c) संविधान सभा की अंतिम आधिकारिक बैठक में 'जन गण मन' को राष्ट्रीय गान तथा 'वंदे मातरम' को राष्ट्रीय गीत के रूप में अंगीकार करने की तिथि

d) संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से डॉ. राजेंद्र प्रसाद को स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति विधिक रूप से चुने जाने की ऐतिहासिक तिथि

सूची II :

1. मई 1949
2. 24 जनवरी 1950
3. 22 जुलाई 1947
4. 26 जनवरी 1950
- 5.

A) a-3, b-1, c-2, d-4

B) a-3, b-1, c-2, d-2

C) a-1, b-3, c-2, d-2

D) a-3, b-4, c-1, d-2

प्रश्न 39: मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों (1919) के तहत केंद्रीय विधायिका के उच्च सदन 'राज्य परिषद' (Council of State) की सांख्यिकीय बनावट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असंगत है?

A) इस सदन की कुल सदस्य संख्या 60 विनिर्दिष्ट की गई थी, जिसमें से 26 सदस्यों को मनोनीत करने का प्रशासनिक अधिकार वायसराय के पास था।

B) राज्य परिषद के भीतर निर्वाचित होने वाले 34 सदस्यों में से 20 सदस्य सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों से चुने जाते थे।

C) इस उच्च सदन के विनियामक नियमों के तहत महिलाओं को सदस्यता प्राप्त करने और मत अंकित करने का पूर्ण विधिक अधिकार प्रदान किया गया था।

D) इसके मताधिकार के मापदंड इतने कठोर थे कि केवल वे ही नागरिक पात्र थे जो न्यूनतम 10,000 रुपये वार्षिक भू-राजस्व देते थे या आयकरदाता थे।

प्रश्न 40: आधुनिक भारत के संविधान के मुख्य शिल्पकार डॉ. बी. आर. अंबेडकर के संविधान सभा में निर्वाचन तथा उनके प्रादेशिक विधायी संस्तर विस्थापन के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान कीजिए:

कथन: विभाजन विलेख (3 जून 1947) के प्रभाव से डॉ. अंबेडकर की सदस्यता समाप्त होने पर उन्हें किस सीट से विधिक त्यागपत्र दिलवाकर उपचुनाव द्वारा पुनः शामिल किया गया था?

- A) बम्बई प्रेसिडेंसी की पुणे सीट से एम. आर. जयकर के विधिक त्यागपत्र द्वारा
- B) बंगाल प्रांत की जेसोर-कुलना सीट से प्रफुल्ल चंद्र घोष के विधिक त्यागपत्र द्वारा
- C) मद्रास प्रेसिडेंसी की कोयम्बटूर सीट से चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के विधिक त्यागपत्र द्वारा
- D) संयुक्त प्रांत की इलाहबाद सीट से पंडित मदन मोहन मालवीय के विधिक त्यागपत्र द्वारा

प्रश्न 41: भारतीय संविधान की राजनैतिक प्रकृति और संघात्मक प्रतिरूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन I : ब्रिटिश न्यायविद के.सी. व्हीयर ने भारतीय राजव्यवस्था को इसके एकात्मक झुकाव के कारण विशुद्ध रूप से 'सौदेबाजी वाले संघवाद' (Bargaining Federalism) की संज्ञा दी है।

कथन II: भारतीय संविधान का प्रथम अनुच्छेद भारत को 'राज्यों का संघ' विनिर्मित करता है, जो अमेरिकी मॉडल के समान संप्रभु राज्यों के बीच हुए एक स्वैच्छिक विलेख का परिणाम है।

कथन III : आपातकालीन घोषणाओं की स्थिति में भारतीय प्रशासनिक ढांचा बिना किसी औपचारिक वैधानिक संशोधन के पूरी तरह से एकात्मक स्वरूप में परिवर्तित हो जाता है।
निम्न में से **कौनसा /कौनसे कथन सत्य है -**

- A) केवल कथन I और II
- B) केवल कथन III
- C) केवल कथन I और III
- D) केवल कथन II

प्रश्न 42: भारतीय संविधान के विदेशी स्रोतों और विभिन्न देशों के वैधानिक विन्यासों के भारतीय पारि-पारिस्थितिकी में अनुकूलन के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथन और कारण पर विचार कीजिए:

कथन: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में समाहित 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' (Procedure Established by Law) का विनियामक विलेख संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल संविधान से ग्रहण किया गया है।

कारण: अमेरिकी संवैधानिक दर्शन मुख्य रूप से 'विधि की उचित प्रक्रिया' (Due Process of Law)

के सिद्धांत पर आधारित है, जो प्राकृतिक न्याय के तत्वों को व्यापक विधिक संरक्षण प्रदान करता है।

- A) कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण, कथन की सही व्याख्या करता है
- B) कथन और कारण दोनों सत्य हैं परंतु कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं करता है
- C) कथन सत्य है परंतु कारण असत्य है
- D) कथन असत्य है परंतु कारण सत्य है

प्रश्न 43: भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं और उसके विनियामक लचीलेपन के संबंध में निम्नलिखित कथनों और निष्कर्षों का मूल्यांकन कीजिए:

कथन: भारतीय संविधान में कठोरता एवं लचीलेपन का एक संतुलित विन्यास निर्मित किया गया है, जिसके तहत कुछ विशिष्ट उपबंधों को संसद सामान्य विधायी प्रक्रिया द्वारा संशोधित कर सकती है।

निष्कर्ष I : संसद द्वारा साधारण बहुमत से किया जाने वाला नए राज्यों का निर्माण या सीमाओं में परिवर्तन अनुच्छेद 368 की विधिक सीमा के अंतर्गत एक औपचारिक संविधान संशोधन माना जाता है।

निष्कर्ष II : संविधान के लचीलेपन की इस विनियामक व्यवस्था के कारण ही प्रख्यात विद्वान आईवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को 'विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत विलेख' कहा था।

- A) केवल निष्कर्ष I सत्य है
- B) केवल निष्कर्ष II सत्य है
- C) निष्कर्ष I और II दोनों असत्य हैं
- D) निष्कर्ष I और II दोनों सत्य हैं

प्रश्न 44: भारतीय संविधान में समाहित विभिन्न दार्शनिक आदर्शों एवं विनियामक प्रावधानों को उनके मूल वैधानिक स्रोतों के साथ सुमेलित कीजिए:

सूची I :

- a) प्रस्तावना में प्रयुक्त 'स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व' के दार्शनिक आदर्श
- b) राष्ट्रपति की विशिष्ट निर्वाचन पद्धति एवं नीति निर्देशक तत्वों का संस्तर
- c) उच्चतम न्यायालय का परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 143) का विन्यास

d) व्यापार, वाणिज्य की स्वतंत्रता तथा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का विलेख

सूची II :

1. आयरलैंड का ऐतिहासिक संविधान
2. कनाडा का संघीय विनियामक ढांचा
3. फ्रांस की गणतांत्रिक राज्यव्यवस्था
4. ऑस्ट्रेलिया का वैधानिक प्रक्रम
- 5.

A) a-3, b-1, c-4, d-2

B) a-3, b-1, c-2, d-4

C) a-1, b-3, c-2, d-4

D) a-4, b-2, c-1, d-3

प्रश्न 45: भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सन्निहित राजनैतिक दर्शन और दार्शनिक आयामों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असंगत है?

- A) प्रस्तावना में वर्णित 'न्याय' का त्रिविध आदर्श (सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक) वर्ष 1917 की रूसी क्रांति के ऐतिहासिक सिद्धांतों से प्रेरित है।
- B) 'हम भारत के लोग' की संप्रभु शब्दावली संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान और संयुक्त राष्ट्र (UN) चार्टर के विन्यास के सदृश प्रदर्शित होती है।
- C) 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा प्रस्तावना में केवल दो नए शब्द 'समाजवादी' और 'पंथनिरपेक्ष' विधिक रूप से अंतःस्थापित किए गए थे।
- D) प्रस्तावना में प्रयुक्त 'गणराज्य' (Republic) शब्द इस विनियामक तथ्य को रेखांकित करता है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्वाचित होगा, वंशानुगत नहीं।

प्रश्न 46: नीचे दिए गए अकादमिक परिच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित एकल विश्लेषणात्मक प्रश्न का उत्तर दीजिए:

"वर्ष 1960 के बेरुबाड़ी संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 8 न्यायाधीशों की पीठ ने प्रस्तावना के विधिक अस्तित्व पर संकुचित दृष्टिकोण अपनाया। न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी तो है, परंतु यह संविधान का विधिक भाग नहीं है।"

उपरोक्त परिच्छेद के आलोक में, वर्ष 1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारती वाद में न्यायपालिका

ने बेरुबाड़ी वाद के निर्णय को उलटते हुए क्या विवर्तनिक विन्यास प्रतिपादित किया?

A) प्रस्तावना केवल एक औपचारिक परिचयात्मक वक्तव्य है, जो केवल साधारण विधायी शक्तियों का मुख्य स्रोत है।

B) प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न और आंतरिक भाग है, जिसके मूल ढांचे को नष्ट किए बिना उसमें विधिक संशोधन किया जा सकता है।

C) प्रस्तावना अनुच्छेद 368 की संशोधनकारी शक्तियों के दायरे से पूरी तरह बाहर एक अपरिवर्तनीय और अलौकिक विलेख है।

D) प्रस्तावना को केवल तभी संशोधित किया जा सकता है जब देश के शत-प्रतिशत राज्यों के विधानमंडल इसे अपनी विशेष विधिक सहमति प्रदान करें।

प्रश्न 47: भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त दार्शनिक शब्द 'पंथनिरपेक्षता' (Secularism) के भारतीय प्रतिरूप के संदर्भ में कौन सा प्रशासनिक विन्यास सत्य है?

A) भारत की पंथनिरपेक्षता पश्चिमी देशों के 'धर्म और राज्य के पूर्ण विच्छेद' के नकारात्मक मॉडल पर आधारित है।

B) राज्य का अपना एक विशिष्ट आधिकारिक धर्म विनिर्दिष्ट है, परंतु वह अल्पसंख्यकों के धार्मिक अधिकारों का आदर करता है।

C) भारत ने 'सकारात्मक पंथनिरपेक्षता' को अपनाया है, जहाँ राज्य सभी धर्मों को समान आदर और विधिक संरक्षण प्रदान करता है।

D) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार एक निरपेक्ष विलेख है, जिस पर लोक व्यवस्था या स्वास्थ्य के आधार पर भी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता।

प्रश्न 48: भारतीय संविधान के एकात्मक झुकाव को प्रदर्शित करने वाले विनियामक लक्षणों और के.सी. व्हीयर के विरोधाभास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन I : एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका और केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति भारतीय संविधान के सशक्त एकात्मक लक्षण हैं।

कथन II: अखिल भारतीय सेवाओं (IAS, IPS) का विन्यास पूरी तरह से प्रांतों की प्रशासनिक संप्रभुता और राजकोषीय स्वायत्तता को सुदृढ़ करने हेतु किया गया था।

कथन III : प्रख्यात विद्वान अलेक्जेंड्रोविच ने के.सी. व्हीयर के विरोधाभास का खंडन करते हुए भारतीय संविधान को एक 'सच्चा संघ' (True Federation) स्वीकार किया है।

निम्न में से **कौनसा / कौनसे कथन सत्य है -**

- A) केवल कथन I और II
- B) केवल कथन II और III
- C) केवल कथन I और III
- D) केवल कथन III

प्रश्न 49: भारतीय संविधान की विस्तृत प्रकृति और उसके वृहद प्रशासनिक विन्यास के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथन और कारण पर विचार कीजिए:

कथन: भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा, विस्तृत और लिखित विन्यास है, जिसमें मूल रूप से 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां शामिल थीं।

कारण: भारत शासन अधिनियम 1935 के व्यापक विधिक दस्तावेज़ का प्रभाव तथा केंद्र और राज्यों दोनों के लिए एक ही 'एकल संविधान' का होना इसकी व्यापकता का प्राथमिक कारण था।

- A) कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण, कथन की सही व्याख्या करता है
- B) कथन और कारण दोनों सत्य हैं परंतु कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं करता है
- C) कथन सत्य है परंतु कारण असत्य है
- D) कथन असत्य है परंतु कारण सत्य है

प्रश्न 50: भारतीय राजव्यवस्था के संघीय सिद्धांतों और शक्तियों के विभाजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों और निष्कर्षों का मूल्यांकन कीजिए:

कथन: भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के माध्यम से विधायी शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है।

निष्कर्ष I : इस शक्तियों के संघीय वितरण के बावजूद, भारत में 'अवशिष्ट शक्तियाँ' (Residuary Powers) अमेरिकी मॉडल के प्रतिरूप राज्यों के पास सुरक्षित रखी गई हैं।

निष्कर्ष II : समवर्ती सूची के विषयों पर यदि केंद्र और राज्य के कानूनों के मध्य विधिक गतिरोध उत्पन्न होता है, तो संघीय कानून को प्रांतीय कानून पर विधिक सर्वोच्चता प्राप्त होती है।

- A) केवल निष्कर्ष I सत्य है
- B) केवल निष्कर्ष II सत्य है
- C) निष्कर्ष I और II दोनों असत्य हैं
- D) निष्कर्ष I और II दोनों सत्य हैं

प्रश्न 51: भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं और विभिन्न देशों से अंगीकार की गई विधिक प्रणालियों को सुमेलित कीजिए:

सूची I :

- a) एकल नागरिकता एवं विधायी प्रक्रिया का वेस्टमिंस्टर प्रतिरूप
- b) विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का विनियामक संस्तर
- c) आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के स्थगन का संकटकालीन प्रावधान
- d) मूल अधिकारों का विलेख, न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं न्यायिक पुनरावलोकन

सूची II :

- 1. जापानी संवैधानिक दर्शन
- 2. जर्मनी का वेइमर संविधान
- 3. ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली
- 4. संयुक्त राज्य अमेरिका का अधिकार पत्र

- A) a-3, b-1, c-4, d-2
- B) a-3, b-1, c-2, d-4
- C) a-1, b-3, c-2, d-4
- D) a-4, b-2, c-1, d-3

प्रश्न 52: भारतीय संविधान की प्रस्तावना की विधिक गतिकी और ऐतिहासिक वादों के न्यायिक दृष्टिकोण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असंगत है?

- A) गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967) वाद में न्यायमूर्ति सुब्बाराव ने प्रस्तावना को संविधान के शाश्वत सिद्धांतों का निचोड़ बताया था।
- B) एल.आई.सी. ऑफ इंडिया वाद (1995) में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती निर्णयों को बदलते हुए माना कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा नहीं है।

C) प्रस्तावना स्वयं में न तो विधायिका की शक्तियों का मूल स्रोत है और न ही यह विधायी शक्तियों पर कोई विधिक निषेध या प्रतिबंध आरोपित करती है।

D) प्रस्तावना की विधिक प्रकृति गैर-न्यायसंगत (Non-justiciable) है, अर्थात् इसके आदर्शों को आधार बनाकर सीधे न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता।

प्रश्न 53: नीचे दिए गए दार्शनिक परिच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित एकल विश्लेषणात्मक प्रश्न का उत्तर दीजिए:

"भारतीय संविधान निर्माताओं ने देश की बहुसांस्कृतिक पारि-पारिस्थितिकी को अक्षुण्ण रखने हेतु एक अनूठा विन्यास तैयार किया। यह दर्शन न तो पूरी तरह ब्रिटेन की तरह लचीला है कि संसद जब चाहे इसे बदल दे, और न ही अमेरिका की तरह अत्यधिक कठोर है कि इसमें संशोधन असंभव हो जाए।"

उपरोक्त परिच्छेद के आलोक में, संविधान के किस उपबंध को संशोधित करने के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ-साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन की वैधानिक आवश्यकता होती है?

- A) संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और संसद में गणपूर्ति (Quorum) के नियमों का निर्धारण।
- B) सातवीं अनुसूची की विधायी सूचियों में कोई भी परिवर्तन या राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति।
- C) राजभाषा का प्रयोग तथा नए राज्यों का प्रवेश, नाम और उनकी सीमाओं का पुनर्गठन।
- D) नागरिकता की प्राप्ति, समाप्ति और संसद में अंग्रेजी भाषा के विनियामक प्रयोग का विलेख।

प्रश्न 54: भारतीय संघवाद की प्रकृति का सूक्ष्म विश्लेषण करने वाले विदेशी राजनीतिक विचारकों और उनकी प्रसिद्ध शब्दावलियों का कौन सा विन्यास सत्य प्रतिरूप को प्रदर्शित करता है?

- A) मौरिस जोन्स: 'सहयोगपूर्ण संघवाद'; ग्रेनविले ऑस्टिन: 'अर्ध-संघात्मक'
- B) मौरिस जोन्स: 'सौदेबाजी वाला संघवाद' (Bargaining Federalism); ग्रेनविले ऑस्टिन: 'सहयोगपूर्ण संघवाद' (Cooperative Federalism)
- C) पॉल एप्पलबी: 'अत्यंत विकेंद्रीकृत संघवाद'; के.सी. व्हीयर: 'पूर्ण संघात्मक राजव्यवस्था'

D) आईवर जेनिंग्स: 'कमजोर केंद्र वाला संघ'; मौरिस जोन्स: 'एकीकृत प्रशासनिक संघवाद'

प्रश्न 55: 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा प्रस्तावना में किए गए शाब्दिक परिवर्तनों और सांख्यिकीय विन्यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन I : इस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में तीन नए शब्दों—'समाजवादी', 'पंथनिरपेक्ष' और 'अखंडता' का समावेश विधिक रूप से किया गया था।

कथन II : संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में पूर्व से विद्यमान शब्दावली "राष्ट्र की एकता" को प्रतिस्थापित करके "राष्ट्र की एकता और अखंडता" विस्थापित किया गया।

कथन III : भारतीय राजव्यवस्था के इतिहास में प्रस्तावना के भीतर अनुच्छेद 368 की संशोधनकारी शक्ति का प्रयोग अब तक कुल तीन बार किया जा चुका है।

निम्न में से कौनसा /कौनसे कथन सत्य है -

- A) केवल कथन I और II
- B) केवल कथन II और III
- C) केवल कथन I और III
- D) केवल कथन II

प्रश्न 56: भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षणों और प्रांतीय स्वायत्तता के विनियामक कवच के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथन और कारण पर विचार कीजिए:

कथन: एक लिखित, विस्तृत और कठोर संविधान का होना किसी भी संघीय शासन व्यवस्था की सुरक्षा हेतु एक अनिवार्य विनियामक रक्षक माना जाता है।

कारण: लिखित और कठोर संविधान केंद्र सरकार को यह संप्रभु शक्ति प्रदान करता है कि वह राज्य सूची के विषयों पर एकपक्षीय विधायी अधिनियमों द्वारा प्रांतों की सीमाओं को समाप्त कर सके।

- A) कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण, कथन की सही व्याख्या करता है
- B) कथन और कारण दोनों सत्य हैं परंतु कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं करता है
- C) कथन सत्य है परंतु कारण असत्य है
- D) कथन असत्य है परंतु कारण सत्य है

प्रश्न 57: प्रस्तावना में सन्निहित 'लोकतंत्र' और 'गणराज्य' के दार्शनिक स्तंभों के संबंध में

निम्नलिखित कथनों और निष्कर्षों का मूल्यांकन कीजिए:

कथन: भारतीय संविधान की प्रस्तावना एक संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतन्त्रात्मक गणराज्य के रूप में राजव्यवस्था के सर्वोच्च स्वरूप की परिकल्पना करती है।

निष्कर्ष I : भारत में 'अप्रत्यक्ष लोकतंत्र' के अंतर्गत संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया है, जहाँ कार्यपालिका अपनी सभी नीतियों के लिए विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है।

निष्कर्ष II : 'गणराज्य' का दार्शनिक कूट यह घोषित करता है कि भारत में राजनीतिक संप्रभुता किसी एक विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के हाथ में निहित होगी।

- A) केवल निष्कर्ष I सत्य है
B) केवल निष्कर्ष II सत्य है
C) निष्कर्ष I और II दोनों असत्य हैं
D) निष्कर्ष I और II दोनों सत्य हैं

प्रश्न 58: भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त दार्शनिक लक्ष्यों और आदर्शों को उनके सही विन्यासक्रम के अनुसार सुमेलित कीजिए:

सूची I :

- a) विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की पंचविध कड़ि
b) सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का त्रिविध आयाम
c) प्रतिष्ठा और अवसर की द्विविध समता का विनियामक विलेख
d) व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने का संकल्प

सूची II :

1. समता (Equality) का दार्शनिक संस्तर
2. बंधुत्व (Fraternity) का वैधानिक विन्यास
3. स्वतंत्रता (Liberty) का मूल आदर्श
4. न्याय (Justice) का मूलाधार

- A) a-3, b-4, c-1, d-2
B) a-3, b-1, c-4, d-2
C) a-4, b-3, c-1, d-2
D) a-1, b-4, c-3, d-2

प्रश्न 59: भारतीय संविधान की विस्तृत प्रकृति और उसके विशाल भौगोलिक-ऐतिहासिक पारि-पारिस्थितिकी विन्यास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असंगत है?

- A) संविधान सभा में विधिक विशेषज्ञों और वकीलों का अत्यधिक सांख्यिकीय भार होने के कारण इसे 'वकीलों का स्वर्ग' (Paradise of Lawyers) भी कहा गया।
B) जम्मू-कश्मीर सहित सभी देशी रियासतों और प्रांतों के लिए प्रारंभ से ही एक एकल एकीकृत संविधान का होना इसकी व्यापकता का एक मुख्य विधिक कारण था।
C) संविधान निर्माताओं ने केवल मूल सिद्धांतों का उल्लेख नहीं किया, बल्कि विस्तृत प्रशासनिक प्रावधानों को भी संहिताबद्ध किया ताकि भविष्य में कोई विनियामक गतिरोध न हो।
D) भारत की विशाल भौगोलिक विविधता, जनसांख्यिकीय आयतन और ऐतिहासिक समस्याओं के शमन हेतु विशेष उपबंधों (जैसे भाग XVI) को जोड़ना इसकी व्यापकता का प्रमाण है।

प्रश्न 60: प्रख्यात ब्रिटिश न्यायविद एन.ए. पालकीवाला द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में प्रयुक्त दार्शनिक संज्ञा निम्नलिखित में से कौन सी है?

- A) यह हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की ऐतिहासिक 'जन्मकुंडली' (Horoscope) है।
B) यह संपूर्ण भारतीय संविधान का एक विशिष्ट और संप्रभु 'परिचय पत्र' (Identity Card) है।
C) यह संविधान का सबसे सम्मानित और पवित्र भाग है, जो उसकी वास्तविक 'आत्मा' को परिलक्षित करता है।
D) यह वह अभेद्य रक्षात्मक विन्यास है जो शासन के अधिनायकवादी झुकाव को विधिक रूप से रोकता है।

प्रश्न 61: भारतीय संविधान के भाग III में संहिताबद्ध मौलिक अधिकारों के अंतर्गत 'समानता के अधिकार' के विनियामक विन्यास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन I : अनुच्छेद 15(6) और 16(6) को 103वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 द्वारा जोड़ा गया, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए लोक नियोजन और शैक्षणिक संस्थाओं में

अधिकतम 15 प्रतिशत आरक्षण का विन्यास किया जा सके।

कथन II: इन्द्रा साहनी बनाम भारत संघ वाद (1992) में सर्वोच्च न्यायालय की 9 न्यायाधीशों की पीठ ने पिछड़ा वर्ग के लिए क्रीमी लेयर की पहचान हेतु विधिक मापदंड स्थापित करने का ऐतिहासिक निर्देश दिया था।

कथन III : एम. नागराज बनाम भारत संघ वाद (2006) में न्यायपालिका ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण हेतु तीन विनियामक शर्तें (पिछड़ापन, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक दक्षता) अनिवार्य की थीं।
निम्न में से **कौनसा /कौनसे कथन सत्य है -**

- A) केवल कथन I और II
- B) केवल कथन II और III
- C) केवल कथन I और III
- D) केवल कथन II

प्रश्न 62: अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सन्निहित 'प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण' के न्यायिक विस्तार तथा विधिक गतिकी के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथन और कारण पर विचार कीजिए:

कथन: मेनका गांधी बनाम भारत संघ वाद (1978) में सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि अनुच्छेद 21 के तहत दैहिक स्वतंत्रता को सीमित करने वाली विधि की प्रक्रिया केवल विधिक रूप से स्थापित होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और अयुक्तिसंगत भी होना चाहिए।

कारण: भारतीय संविधान निर्माताओं ने जापानी संविधान के प्रतिरूप 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' की शब्दावली को स्वेच्छा से त्यागकर अमेरिकी संवैधानिक विन्यास 'विधि की उचित प्रक्रिया' को मूल पाठ में विस्थापित किया था।

- A) कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण, कथन की सही व्याख्या करता है
- B) कथन और कारण दोनों सत्य हैं परंतु कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं करता है
- C) कथन सत्य है परंतु कारण असत्य है
- D) कथन असत्य है परंतु कारण सत्य है

प्रश्न 63: अनुच्छेद 32 के संवैधानिक उपचारों के अधिकार तथा न्यायपालिका की असाधारण रिट जारी करने की संप्रभु विधिक शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों और निष्कर्षों का मूल्यांकन कीजिए:

कथन: अनुच्छेद 32 स्वयं में एक मौलिक अधिकार है जो नागरिकों को अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का विधिक उपचार सुनिश्चित करता है, जिसे आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति के आदेश द्वारा ही निलंबित किया जा सकता है।

निष्कर्ष I : अनुच्छेद 32 के तहत प्राप्त रिट क्षेत्राधिकार का आयतन विधिक रूप से अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को प्राप्त रिट क्षेत्राधिकार के आयतन की तुलना में अधिक विस्तृत विन्यासित है।

निष्कर्ष II : यदि किसी नागरिक के विधिक सिविल अधिकारों का ह्रास होता है जो मौलिक अधिकारों की श्रेणी में नहीं आते, तो वह सीधे अनुच्छेद 32 के तहत रिट उपचार प्राप्त करने हेतु विधिक रूप से अपात्र माना जाएगा।

- A) केवल निष्कर्ष I सत्य है
- B) केवल निष्कर्ष II सत्य है
- C) निष्कर्ष I और II दोनों असत्य हैं
- D) निष्कर्ष I और II दोनों सत्य हैं

प्रश्न 64: राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSP) में सन्निहित विभिन्न समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक सिद्धांतों को उनके विनिर्दिष्ट अनुच्छेदों के साथ सुमेलित कीजिए:

सूची I :

- a) समस्त भारत के राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता (UCC) सुनिश्चित करने का विन्यास
- b) उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की प्रभावी भागीदारी को प्रोत्साहित करने का वैधानिक निर्देश
- c) सभी बालकों को छह वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा प्रदान करने का दायित्व
- d) ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को कुटीर स्तर पर प्रोत्साहन देना

सूची II :

1. अनुच्छेद 43-A (42वें संविधान संशोधन द्वारा अंतःस्थापित)
2. अनुच्छेद 43 की गांधीवादी मेखला
3. अनुच्छेद 44 का धर्मनिरपेक्ष दार्शनिक आयाम
4. अनुच्छेद 45 (86वें संविधान संशोधन द्वारा संशोधित स्वरूप)

- A) a-3, b-1, c-2, d-4
B) a-3, b-1, c-4, d-2
C) a-1, b-3, c-4, d-2
D) a-4, b-2, c-1, d-3

प्रश्न 65: मौलिक कर्तव्यों (भाग IV-A) के दार्शनिक विनिर्माण, सांस्थानिक सिफारिशों और नागरिक चेतना पारिस्थितिकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असंगत है?

A) सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने वर्ष 1976 में आठ मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश के साथ-साथ कर्तव्यों का पालन न करने पर विधायी दंड और कर अदायगी को कर्तव्य बनाने का विधिक सुझाव दिया था।

B) 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान में भाग IV-A और अनुच्छेद 51-A को अंतःस्थापित करके नागरिकों हेतु सांख्यिकीय रूप से 11 मौलिक कर्तव्यों का एक अभेद्य विन्यास किया गया।

C) न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा समिति (1999) ने राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विभिन्न प्रवर्तमान दंडात्मक विधिक अधिनियमों की पहचान कर उनके क्रियान्वयन को रेखांकित किया था।

D) मौलिक कर्तव्यों का विनियामक स्वरूप केवल भारत के संप्रभु नागरिकों पर ही विधिक रूप से बाध्यकारी है, यह क्षेत्राधिकार भारत में रहने वाले विदेशी नागरिकों पर विस्तारित नहीं होता है।

प्रश्न 66: नीचे दिए गए अकादमिक परिच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित एकल विश्लेषणात्मक प्रश्न का उत्तर दीजिए:

"अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संघीय ढांचे को प्रभावित करने वाले संवैधानिक उपबंधों को संशोधित करने हेतु संसद के विशेष बहुमत के साथ-साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन की अनिवार्य विनियामक शर्त विस्थापित है। यह

प्रक्रिया केंद्र और राज्यों के बीच विधायी और राजकोषीय शक्तियों के आनुपातिक संतुलन को अक्षुण्ण रखती है।"

उपरोक्त परिच्छेद के विलेख विन्यास के आलोक में, निम्नलिखित में से किस विषय में संशोधन करने हेतु आधे राज्यों के वैधानिक समर्थन का यह प्रतिरूप अनिवार्य रूप से लागू होगा?

- A) अनुच्छेद 169 के तहत किसी राज्य में विधान परिषद का विनिर्माण अथवा उसकी समाप्ति की विधायी प्रक्रिया।
B) संसद में गणपूर्ति (Quorum) के नियमों का निर्धारण तथा संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों का विनियामक संस्तर।
C) सातवीं अनुसूची की किसी भी विधायी सूची में कोई परिवर्तन अथवा राष्ट्रपति के निर्वाचन की विनिर्दिष्ट पद्धति।
D) नागरिकता की प्राप्ति और उसकी वैधानिक समाप्ति तथा संसद में अंग्रेजी भाषा के प्रयोग की समय सीमा का विस्तार।

प्रश्न 67: अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त छह लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं और उन पर राज्य द्वारा आरोपित किए जाने वाले 'युक्तिसंगत निर्बंधनों' के संदर्भ में कौन सा प्रशासनिक विन्यास सत्य प्रतिरूप प्रदर्शित करता है?

- A) भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19(1)(a)) एक निरपेक्ष विलेख है, जिस पर देश की सुरक्षा के नाम पर भी कोई पूर्व-संश्लेषण लागू नहीं की जा सकती है।
B) भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण और निवास करने की स्वतंत्रता पर आम जनता के हित या किसी अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण हेतु विधिक रोक लगाई जा सकती है।
C) संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत विधिक रूप से 'हड़ताल करने का अधिकार' (Right to Strike) और तालाबंदी की घोषणा एक मौलिक अधिकार के रूप में अंतर्निहित है।
D) कोई वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता के अंतर्गत राज्य को किसी भी व्यवसाय का पूर्णतः राष्ट्रीयकरण करने या उसे निजी क्षेत्र से विमुक्त करने की विधायी शक्ति प्राप्त नहीं है।

प्रश्न 68: शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24) और मानवीय गरिमा के विनियामक

संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन I : अनुच्छेद 23 के तहत प्रतिबंधित 'बेगार' का विधिक अर्थ केवल शारीरिक शक्ति द्वारा कराया गया अनिवार्य काम है, आर्थिक विवशता के कारण न्यूनतम मजदूरी से कम पर कराया गया कार्य इसके दायरे से बाहर है।

कथन II: राज्य को सार्वजनिक उद्देश्यों (जैसे सैन्य सेवा या सामाजिक सेवा) के लिए नागरिकों पर अनिवार्य सेवा लागू करने की संप्रभु शक्ति है, बशर्ते वह धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव न करे।

कथन III : बाल श्रम (निषेध एवं नियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 के प्रवर्तन के पश्चात अब 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को सभी व्यवसायों में नियोजित करना पूर्णतः प्रतिबंधित है, केवल स्कूल के समय के बाद पारिवारिक उद्यमों को छोड़कर। निम्न में से **कौनसा /कौनसे कथन सत्य है -**

- A) केवल कथन I और II
- B) केवल कथन II और III
- C) केवल कथन I और III
- D) केवल कथन II

प्रश्न 69: अनुच्छेद 25 से 28 के धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार और भारतीय सकारात्मक पंथनिरपेक्षता (Secularism) के विनियामक ढांचे के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथन और कारण पर विचार कीजिए:

कथन: स्टेनिसलॉस बनाम मध्य प्रदेश राज्य वाद (1977) में सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि अनुच्छेद 25 में समाहित 'धर्म के प्रचार करने के अधिकार' में किसी अन्य व्यक्ति का जबरन या प्रलोभन द्वारा धर्मांतरण कराने का विधिक अधिकार शामिल नहीं है।

कारण: भारत की सकारात्मक पंथनिरपेक्षता सर्व धर्म समभाव के सिद्धांत पर आधारित है, जहाँ राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर का भुगतान करने हेतु विवश नहीं कर सकता जिसका उपयोग किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि हेतु किया जाना विनिर्दिष्ट हो।

- A) कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण, कथन की सही व्याख्या करता है
- B) कथन और कारण दोनों सत्य हैं परंतु कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं करता है
- C) कथन सत्य है परंतु कारण असत्य है
- D) कथन असत्य है परंतु कारण सत्य है

प्रश्न 70: मौलिक अधिकारों (भाग III) और राज्य के नीति निदेशक तत्वों (भाग IV) के मध्य प्राथमिकता के विधिक गतिरोध को सुलझाने वाले न्यायिक निर्णयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों और निष्कर्षों का मूल्यांकन कीजिए:

कथन: 25वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1971 द्वारा अंतःस्थापित अनुच्छेद 31-C ने प्रावधान किया कि अनुच्छेद 39(b) और 39(c) के समाजवादी सिद्धांतों को लागू करने हेतु बनाई गई विधियों को अनुच्छेद 14, 19 और 31 के उल्लंघन के आधार पर शून्य नहीं घोषित किया जाएगा।

निष्कर्ष I : चंपकम दोराईराजन वाद (1951) में सर्वोच्च न्यायालय ने यह युगांतरकारी विलेख प्रतिपादित किया कि नीति निदेशक तत्व मौलिक अधिकारों पर सदैव प्रभावी और सर्वोच्च विधिक स्थिति में रहेंगे।

निष्कर्ष II : मिनर्वा मिल्स वाद (1980) में न्यायपालिका ने 42वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31-C के किए गए अत्यधिक विस्तार को असंवैधानिक घोषित कर मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों के मध्य संतुलन को मूल ढांचा माना।

- A) केवल निष्कर्ष I सत्य है
- B) केवल निष्कर्ष II सत्य है
- C) निष्कर्ष I और II दोनों असत्य हैं
- D) निष्कर्ष I और II दोनों सत्य हैं

प्रश्न 71: भारतीय न्यायिक तंत्र द्वारा मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु जारी की जाने वाली विभिन्न विशिष्ट श्रेणियों की 'रिट' (Writs) को उनके विधिक क्षेत्राधिकार के प्रतिरूप के साथ सुमेलित कीजिए:

सूची I :

- a) किसी सार्वजनिक अधिकारी को उसके विधिक कर्तव्यों के अनिवार्य निर्हवन हेतु उच्च न्यायिक पीठ द्वारा जारी आदेश कूट

- b) किसी व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से किसी सार्वजनिक विनियामक पद को धारण करने की वैधानिक वैधता की जांच करने हेतु प्रयुक्त रिट
c) किसी अधीनस्थ न्यायालय या अर्ध-न्यायिक निकाय को अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण करने से रोकने हेतु गतिक होने वाली रिट
d) अधीनस्थ न्यायालय में लंबित किसी वाद को विधिक संवीक्षा हेतु उच्चतर न्यायालय में स्थानांतरित करने का न्यायिक आदेश

सूची II :

1. प्रतिषेध (Prohibition - क्षेत्राधिकार के हास को रोकने हेतु)
2. उत्प्रेषण (Certiorari - सुधारात्मक एवं विनियामक प्रकृति की)
3. अधिकार पृच्छा (Quo-Warranto - विधिक वारंट की संवीक्षा)
4. परमादेश (Mandamus - हम आज्ञा देते हैं)

- A) a-4, b-3, c-2, d-1
B) a-4, b-3, c-1, d-2
C) a-1, b-2, c-3, d-4
D) a-3, b-4, c-1, d-2

प्रश्न 72: 86वें संविधान संशोधन अधिनियम (2002) द्वारा शिक्षा के अधिकार के त्रिविध विन्यास और उससे जनित नागरिक चेतना पारिस्थितिकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असंगत है?

- A) इस संशोधन ने भाग III के तहत अनुच्छेद 21-A को अंतःस्थापित करके 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया।
B) संशोधन ने भाग IV के तहत अनुच्छेद 45 की विषय-वस्तु को परिवर्तित कर दिया, जिसके अनुसार राज्य सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा।
C) 86वें संशोधन के विनिर्देशों को व्यावहारिक रूप से लागू करने हेतु संसद द्वारा 'शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE)' वर्ष 2005 में पारित कर 1 अप्रैल 2006 से पूरे देश में प्रभावी किया गया था।
D) इसने अनुच्छेद 51-A के तहत खंड (k) को जोड़कर प्रत्येक माता-पिता या संरक्षक का यह

नागरिक कर्तव्य बनाया कि वे अपने 6 से 14 वर्ष तक के प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करें।

प्रश्न 73: नीचे दिए गए विधिक परिच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित एकल विश्लेषणात्मक प्रश्न का उत्तर दीजिए:

"अनुच्छेद 20(3) अभियुक्तों को आत्म-अभिशंसन से संरक्षण (Protection against Self-incrimination) प्रदान करता है, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। सेलवी बनाम कर्नाटक राज्य वाद (2010) में न्यायालय ने इसके वैज्ञानिक अनुप्रयोगों की विस्तृत व्याख्या की।"

उपरोक्त परिच्छेद के आलोक में, सेलवी वाद (2010) में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक को अभियुक्त की सहमति के बिना कराया जाना अनुच्छेद 20(3) का विधिक उल्लंघन माना है?

- A) नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफ टेस्ट (झूठ पकड़ने की मशीन) और ब्रेन मैपिंग तकनीक।
B) केवल उंगलियों के निशान (Fingerprints) और लिखावट के नमूनों का प्रशासनिक संकलन।
C) किसी आपराधिक मामले की जांच हेतु न्यायालय के आदेश पर अभियुक्त के रक्त के नमूनों का विधिक विश्लेषण।
D) लोक व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से किसी संदिग्ध व्यक्ति के चेहरे की डिजिटल पहचान (Facial Recognition)।

प्रश्न 74: अनुच्छेद 22 के तहत प्राप्त 'गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण' तथा निवारक निरोध (Preventive Detention) की विनियामक सीमाओं के संबंध में कौन सा विन्यास विधिक रूप से सत्य है?

- A) सामान्य दंडिक विधि के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को यात्रा के समय को शामिल करके 12 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना अनिवार्य विन्यासित है।
B) निवारक निरोध कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को बिना किसी सलाहकार बोर्ड की संस्तुति के अधिकतम 6 माह की अवधि तक हिरासत में रखा जा सकता है।

C) निवारक निरोध के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को यह विधिक अधिकार प्राप्त है कि वह अपनी गिरफ्तारी के आधारों को जानने हेतु राज्य से संपर्क कर सके, बशर्ते वह लोक हित के विरुद्ध न हो।

D) निवारक निरोध कानून बनाने की विधायी संप्रभुता केवल भारत की संसद के पास अनन्य रूप से सुरक्षित है, राज्यों के विधानमंडलों को इस विषय पर कानून बनाने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है।

प्रश्न 75: अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रियात्मक गतिकी और संसद की विधायी सीमाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन I : संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में अथवा किसी भी राज्य के विधानमंडल में मंत्रियों या निजी सदस्यों द्वारा बिना राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के प्रस्तुत किया जा सकता है।

कथन II: संविधान संशोधन विधेयक को दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग विशेष बहुमत से पारित किया जाना अनिवार्य है; दोनों सदनों के मध्य विधायी गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक (Joint Sitting) बुलाने का कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है।

कथन III : 24वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1971 के प्रवर्तन के पश्चात संसद द्वारा पारित होकर आए संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी विधिक सहमति देने हेतु बाध्य हैं, वे इसे पुनर्विचार हेतु वापस नहीं भेज सकते।
निम्न में से **कौनसा /कौनसे कथन सत्य है -**

- A) केवल कथन I और II
- B) केवल कथन II
- C) केवल कथन II और III
- D) केवल कथन III

प्रश्न 76: अनुच्छेद 20 के अंतर्गत प्रदत्त 'कार्योत्तर विधियों से संरक्षण' (Ex-Post Facto Laws) के विनियामक ढांचे तथा आपराधिक न्याय प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथन और कारण पर विचार कीजिए:

कथन: राज्य किसी भी व्यक्ति को किसी ऐसे कृत्य के लिए आपराधिक रूप से दंडित नहीं कर सकता जो उस कृत्य को किए जाने के समय लागू किसी प्रवर्तमान विधिक कानून के तहत अपराध की श्रेणी में शामिल नहीं था।

कारण: कार्योत्तर विधियों से मिलने वाला यह संवैधानिक संरक्षण केवल दंडात्मक आपराधिक कानूनों (Criminal Laws) तक ही सीमित है, राज्य दीवानी कानूनों (Civil Laws) या कर कानूनों (Tax Laws) को पिछली तारीख से लागू करने हेतु विधिक रूप से पूर्णतः स्वतंत्र है।

- A) कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण, कथन की सही व्याख्या करता है
- B) कथन और कारण दोनों सत्य हैं परंतु कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं करता है
- C) कथन सत्य है परंतु कारण असत्य है
- D) कथन असत्य है परंतु कारण सत्य है

प्रश्न 77: केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद (1973) के ऐतिहासिक निर्णय तथा 'मूल ढांचे के सिद्धांत' (Basic Structure Doctrine) के दूरगामी विनियामक प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथन और निष्कर्षों का मूल्यांकन कीजिए:

कथन: 24 अप्रैल 1973 को सर्वोच्च न्यायालय की 13 न्यायाधीशों की पीठ ने 7:6 के बहुमत से यह विधिक दर्शन प्रतिपादित किया कि संसद की अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन करने की शक्ति व्यापक तो है, परंतु वह असीमित नहीं है।

निष्कर्ष I : मूल ढांचे के सिद्धांत के उदय के पश्चात न्यायपालिका ने संसद की संशोधनकारी शक्ति को पूरी तरह समाप्त कर दिया, जिससे संविधान एक जड़ विलेख में परिवर्तित हो गया।

निष्कर्ष II : संसद प्रस्तावना में निहित उन मूलभूत दार्शनिक स्तंभों (जैसे पंथनिरपेक्षता, लोकतंत्र, गणराज्य) को विधायी संशोधनों द्वारा विखंडित नहीं कर सकती जो मूल ढांचे का हिस्सा घोषित किए जा चुके हैं।

- A) केवल निष्कर्ष I सत्य है
- B) केवल निष्कर्ष II सत्य है
- C) निष्कर्ष I और II दोनों असत्य हैं
- D) निष्कर्ष I और II दोनों सत्य हैं

प्रश्न 78: मौलिक अधिकारों के अंतर्गत 'धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार' की विभिन्न आंतरिक विनियामक कड़ियों को उनके विनिर्दिष्ट विधिक प्रावधानों के साथ सुमेलित कीजिए:

सूची I :

- a) अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विन्यास
- b) धार्मिक संप्रदायों को अपने धार्मिक मामलों के स्वयं प्रबंधन करने तथा चल-अचल संपत्ति के अर्जन का सामूहिक अधिकार
- c) किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि या पोषण के लिए करों (Taxes) के भुगतान से मुक्ति की विनियामक स्वतंत्रता
- d) राज्य निधि से पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्थाओं में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा प्रदान किए जाने पर पूर्ण वैधानिक प्रतिबंध

सूची II :

- 1. अनुच्छेद 26 का सामूहिक संस्तर
- 2. अनुच्छेद 27 का राजकोषीय पंथनिरपेक्ष आयाम
- 3. अनुच्छेद 28 का शैक्षणिक विन्यास
- 4. अनुच्छेद 25 की व्यक्तिगत धार्मिक मेखला

A) a-4, b-1, c-3, d-2

B) a-4, b-1, c-2, d-3

C) a-1, b-4, c-2, d-3

D) a-3, b-4, c-1, d-2

प्रश्न 79: राज्य के नीति निदेशक तत्वों (भाग IV) के अंतर्गत सन्निहित विभिन्न लोक-कल्याणकारी प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असंगत है?

A) अनुच्छेद 38 के अनुसार, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए ऐसी सामाजिक व्यवस्था का विनिर्माण करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रत्येक नागरिक को सुनिश्चित हो सके।

B) अनुच्छेद 39(d) पुरुषों और स्त्रियों दोनों के लिए 'समान कार्य के लिए समान वेतन' सुनिश्चित करने का एक अभेद्य समाजवादी विधिक निर्देश प्रदान करता है।

C) 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा अंतःस्थापित अनुच्छेद 48-A राज्य को पर्यावरण के

संरक्षण, संवर्धन तथा वन एवं वन्यजीवों की रक्षा करने का संवैधानिक दायित्व सौंपता है।

D) अनुच्छेद 50 के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करने तथा राष्ट्रों के मध्य न्यायसंगत संबंधों को बनाए रखने के उदार बौद्धिक सिद्धांतों को संहिताबद्ध किया गया है।

प्रश्न 80: भारतीय नागरिक चेतना पारिस्थितिकी में समाहित 'मौलिक कर्तव्यों' (Fundamental Duties) की विधिक प्रकृति, प्रवर्तनीयता और सीमाओं के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान कीजिए:

A) मौलिक कर्तव्य विधिक रूप से वादयोग्य (Justiciable) हैं, जिसके कारण उनके उल्लंघन पर कोई भी नागरिक सीधे अनुच्छेद 32 के तहत रिट उपचार प्राप्त कर सकता है।

B) मौलिक कर्तव्यों का समावेश भारत के मूल संवैधानिक पाठ (1950) में ही किया गया था, जिसे बाद में स्वर्ण सिंह समिति ने केवल सांख्यिकीय रूप से विस्तारित किया था।

C) यद्यपि मौलिक कर्तव्य स्वतः प्रवर्तनीय नहीं हैं, फिर भी संसद उपयुक्त विधायी अधिनियम विनिर्मित करके उनके क्रियान्वयन हेतु दंडात्मक अवरोध स्थापित करने की पूर्ण शक्ति रखती है।

D) वर्तमान भारतीय राजव्यवस्था में भाग IV-A के तहत केवल 10 मौलिक कर्तव्य ही संहिताबद्ध हैं, क्योंकि 11वें कर्तव्य को न्यायपालिका ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था।

प्रश्न 81: 'मूल ढांचे' (Basic Structure) के सिद्धांत के विवर्तनिक विन्यास और न्यायिक पुनरावलोकन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन I : गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाद (1967) में सर्वोच्च न्यायालय की 11 न्यायाधीशों की पीठ ने यह विधिक सिद्धांत प्रतिपादित किया था कि संसद अनुच्छेद 368 का प्रयोग करके भाग III के मौलिक अधिकारों को न तो छीन सकती है और न ही सीमित कर सकती है।

कथन II: मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ वाद (1980) में न्यायपालिका ने यह ऐतिहासिक व्यवस्था दी कि 'न्यायिक पुनरावलोकन' स्वयं संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है, अतः संसद विशेष विधायी संकल्प द्वारा इसे प्रतिबंधित कर सकती है।

कथन III : वामन राव बनाम भारत संघ वाद (1981) में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचे के सिद्धांत

के अनुप्रयोग की समय सीमा स्पष्ट करते हुए घोषित किया कि यह सिद्धांत 24 अप्रैल 1973 के बाद पारित होने वाले सभी संविधान संशोधनों पर विधिक रूप से लागू होगा।
निम्न में से कौनसा /कौनसे कथन सत्य है -

- A) केवल कथन I और II
- B) केवल कथन I और III
- C) केवल कथन II और III
- D) केवल कथन II

प्रश्न 82: भारतीय संघीय ढांचे के अंतर्गत केंद्र-राज्य विधिक और प्रशासनिक संबंधों के विनियामक ढांचे के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथन और कारण पर विचार कीजिए:

कथन: अनुच्छेद 365 के विन्यास के अनुसार, यदि कोई राज्य केंद्र सरकार द्वारा दिए गए विधिक संवैधानिक निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है, तो राष्ट्रपति वहां वैधानिक रूप से संवैधानिक तंत्र की विफलता (राष्ट्रपति शासन) मान सकते हैं।

कारण: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 256 केंद्र सरकार की कार्यपालिका को यह संप्रभु शक्ति देता है कि वह राज्य सूची के सभी विशिष्ट लोक-व्यवस्था विषयों पर प्रांतीय प्रशासन को सीधे अपने विवेकाधीन आदेश जारी कर सके।

- A) कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण, कथन की सही व्याख्या करता है
- B) कथन और कारण दोनों सत्य हैं परंतु कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं करता है
- C) कथन सत्य है परंतु कारण असत्य है
- D) कथन असत्य है परंतु कारण सत्य है

प्रश्न 83: अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों के विनियामक नियमन और अनुच्छेद 262 के विधायी नियंत्रण के संबंध में निम्नलिखित कथनों और निष्कर्षों का मूल्यांकन कीजिए:

कथन: अनुच्छेद 262 के अंतर्गत संसद कानून बनाकर अंतर-राज्यीय नदी या नदी घाटी के जल के उपयोग और नियंत्रण संबंधी विवादों के न्यायनिर्णयन हेतु विशिष्ट न्यायाधिकरण गठित कर सकती है।

निष्कर्ष I : अंतर-राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 के तहत गठित न्यायाधिकरण का निर्णय

अंतिम होता है और पीड़ित राज्य इसके विरुद्ध सीधे अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर करने का अनन्य विधिक अधिकार रखता है।

निष्कर्ष II : नदी बोर्ड अधिनियम, 1956 का मुख्य उद्देश्य केवल दो राज्यों के मध्य वित्तीय गतिरोधों को दूर करने हेतु अंतःप्रांतीय करों के आनुपातिक वितरण का नियमन करना विनिर्दिष्ट है।

- A) केवल निष्कर्ष I सत्य है
- B) केवल निष्कर्ष II सत्य है
- C) निष्कर्ष I और II दोनों असत्य हैं
- D) निष्कर्ष I और II दोनों सत्य हैं

प्रश्न 84: राजकोषीय संघवाद तथा अंतर-राज्यीय संबंधों से जुड़े विभिन्न विनियामक निकायों को उनके वैधानिक मूलाधारों के साथ सुमेलित कीजिए:

सूची I :

- a) वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद का वैधानिक विन्यास
- b) राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय संसाधनों के आनुपातिक हस्तांतरण हेतु उत्तरदायी वित्त आयोग
- c) भाषाई और प्रादेशिक तनावों के शमन हेतु विनिर्मित क्षेत्रीय परिषदें
- d) केंद्र और राज्यों के बीच साझा हितों के विषयों पर समन्वय स्थापित करने वाली अंतर-राज्यीय परिषद

सूची II :

- 1. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280
- 2. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 263
- 3. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 279A
- 4. संसदीय वैधानिक अधिनियम (राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956)

- A) a-3, b-1, c-2, d-4
- B) a-3, b-1, c-4, d-2
- C) a-1, b-3, c-4, d-2
- D) a-4, b-2, c-1, d-3

प्रश्न 85: आपातकालीन प्रावधानों (अनुच्छेद 352-360) के संघीय ढांचे पर पड़ने वाले सामरिक प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असंगत है?

- A) सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) के दौरान अनुच्छेद

19 द्वारा प्रदत्त छह लोकतांत्रिक स्वतंत्रताएं स्वतः विधिक रूप से निलंबित नहीं होती हैं।

B) अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति विशेष आदेश जारी करके अनुच्छेद 20 और 21 के प्रवर्तन हेतु नागरिकों के न्यायालय जाने के मौलिक अधिकार को भी निलंबित करने की संप्रभु शक्ति रखते हैं।

C) वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360) के प्रभावी होने पर राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों में कटौती का विनियामक निर्देश दे सकते हैं।

D) राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद द्वारा राज्य सूची के विषयों पर निर्मित विधियां आपातकालीन उद्घोषणा की समाप्ति के 6 माह बाद विधिक रूप से स्वतः निष्प्रभावी हो जाती हैं।

प्रश्न 86: नीचे दिए गए प्रशासनिक परिच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित एकल विश्लेषणात्मक प्रश्न का उत्तर दीजिए:

"101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्थापित GST परिषद अप्रत्यक्ष कराधान प्रणाली की सर्वोच्च संघीय संस्था है। परिषद की बैठक हेतु कुल सदस्यों का 50% कोरम अनिवार्य है और प्रत्येक विनियामक निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 75% भारित बहुमत द्वारा ही पारित किया जा सकता है।"

उपरोक्त वोट मूल्य विन्यास के आधार पर, यदि भारत के समस्त राज्य (2/3 मत मूल्य धारक) एकमत होकर किसी कर स्लैब में बदलाव का संकल्प पारित करना चाहें, लेकिन केंद्र सरकार (1/3 मत मूल्य धारक) असहमत हो, तो विधिक स्थिति क्या होगी?

A) निर्णय बहुमत से पारित माना जाएगा क्योंकि राज्यों के पास दो-तिहाई का विशाल बहुमत उपलब्ध है।

B) निर्णय पारित नहीं हो सकेगा क्योंकि राज्यों का संयुक्त वोट मूल्य 75% के अनिवार्य विनियामक मानदंड से कम है।

C) इस विधायी गतिरोध को सुलझाने हेतु मामले को अंतिम संपुष्टि के लिए नीति आयोग की शासी परिषद को भेजा जाएगा।

D) केंद्रीय वित्त मंत्री के पास अनन्य वीटो शक्ति होने के कारण निर्णय स्वतः ही निरस्त मान लिया जाएगा।

प्रश्न 87: सातवीं अनुसूची के वित्तीय विन्यास और करों के आनुपातिक वितरण प्रतिरूप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य प्रतिरूप को प्रदर्शित करता है?

A) अनुच्छेद 268 के तहत स्टांप शुल्क और औषधीय प्रसाधनों पर कर केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं, परंतु राज्यों द्वारा एकत्र और उपभोग किए जाते हैं।

B) अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान लगने वाले कर (अनुच्छेद 269) राज्यों द्वारा अधिरोपित किए जाते हैं और केंद्र द्वारा वितरित होते हैं।

C) कृषि आय पर लगने वाला कर पूर्णतः संघ सूची का विषय है जिसे केंद्र और राज्यों के बीच आनुपातिक रूप से विभाजित किया जाता है।

D) विदेशी व्यापार से अर्जित होने वाला सीमा शुल्क (Customs Duty) समवर्ती सूची का हिस्सा है जिस पर दोनों का साझा नियंत्रण विन्यासित है।

प्रश्न 88: 16वें वित्त आयोग के गठन, संदर्भ शर्तों (ToR) और वित्तीय हस्तांतरण के मानकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन I : डॉ. अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता में गठित 16वां वित्त आयोग अपनी विस्तृत सिफारिशों की रिपोर्ट 31 अक्टूबर 2025 तक राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

कथन II: 15वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों के लंबवत हस्तांतरण (Vertical Devolution) के अंतर्गत राज्यों की कुल हिस्सेदारी को सांख्यिकीय रूप से 45% निर्धारित किया था।

कथन III : 16वें वित्त आयोग को आपदा प्रबंधन पहलों से संबंधित वर्तमान वित्तपोषण व्यवस्थाओं की समीक्षा करने और सुधारात्मक उपाय सुझाने का कार्य भी सौंपा गया है।

निम्न में से **कौनसा/कौनसे कथन सत्य है -**

A) केवल कथन I और II

B) केवल कथन II और III

C) केवल कथन I और III

D) केवल कथन III

प्रश्न 89: राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) की विधिक प्रासंगिकता और एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ वाद (1994) के न्यायिक विन्यास के

संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथन और कारण पर विचार कीजिए:

कथन: एस.आर. बोम्मई वाद में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात, राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 356 के तहत की गई उद्घोषणा और उसके सहायक कारण पूरी तरह से न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन हैं।

कारण: न्यायालय ने इस ऐतिहासिक वाद में यह स्पष्ट विनियामक निर्देश दिया था कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा होते ही राज्य की विधानसभा को तुरंत प्रभाव से विधिक रूप से भंग कर दिया जाना चाहिए।

- A) कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण, कथन की सही व्याख्या करता है
B) कथन और कारण दोनों सत्य हैं परंतु कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं करता है
C) कथन सत्य है परंतु कारण असत्य है
D) कथन असत्य है परंतु कारण सत्य है

प्रश्न 90: क्षेत्रीय परिषदों (Zonal Councils) के भौगोलिक विन्यास और उनके प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों और निष्कर्षों का मूल्यांकन कीजिए:

कथन: संसदीय वैधानिक अधिनियम द्वारा निर्मित पांच क्षेत्रीय परिषदें अंतर-प्रांतीय समन्वय स्थापित करने वाली महत्वपूर्ण इकाइयाँ हैं, जिनका प्रशासनिक नियंत्रण केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन होता है।

निष्कर्ष I : भारत के केंद्रीय गृह मंत्री इन सभी पांचों क्षेत्रीय परिषदों के साझा अध्यक्ष (Common Chairman) के रूप में विधिक रूप से कार्य करते हैं।

निष्कर्ष II : राजस्थान राज्य को इसके भौगोलिक विन्यास के कारण 'मध्य क्षेत्रीय परिषद' (Central Zonal Council) के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

- A) केवल निष्कर्ष I सत्य है
B) केवल निष्कर्ष II सत्य है
C) निष्कर्ष I और II दोनों असत्य हैं
D) निष्कर्ष I और II दोनों सत्य हैं

प्रश्न 91: अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों के शमन हेतु गठित न्यायाधिकरणों को उनके विनिर्दिष्ट संबद्ध राज्यों की श्रेणियों के साथ सुमेलित कीजिए:

सूची I :

- a) नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का विनियामक क्षेत्राधिकार
b) महादयी जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतर्गत आने वाले राज्य
c) कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण से जुड़े प्रादेशिक संस्तर
d) कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के विधिक पक्षकार राज्य

सूची II :

1. गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र की प्रादेशिक मेखला
2. राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का विन्यास
3. कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र
4. महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का नदी संस्तर

A) a-2, b-1, c-3, d-4

B) a-2, b-1, c-4, d-3

C) a-1, b-3, c-4, d-2

D) a-3, b-4, c-1, d-2

प्रश्न 92: भारतीय संघीय ढांचे में केंद्र-राज्य संबंधों और प्रशासनिक गतिकी के सुधार हेतु गठित विभिन्न आयोगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असंगत है?

A) सरकारी आयोग (1983) ने दृढ़ता से सिफारिश की थी कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में केवल अंतिम विकल्प (Last Resort) के रूप में होना चाहिए।

B) तमिलनाडु सरकार द्वारा गठित राजमंत्रार समिति (1969) ने अवशिष्ट शक्तियों (Residuary Powers) को केंद्र के पास ही और सुदृढ़ रूप से बनाए रखने की वकालत की थी।

C) मदन मोहन पुंछी आयोग (2007) ने राज्यपालों के गरिमापूर्ण पद आर्डर हेतु उन्हें पांच वर्ष का निश्चित कार्यकाल देने और महाभियोग जैसी प्रक्रिया का प्रस्ताव दिया था।

D) प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (1966) ने शक्तियों के संतुलन हेतु अनुच्छेद 263 के अंतर्गत एक स्थायी अंतर-राज्यीय परिषद के गठन की वैधानिक संस्तुति की थी।

प्रश्न 93: नीचे दिए गए राजकोषीय परिच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित एकल विश्लेषणात्मक प्रश्न का उत्तर दीजिए:

"15वें वित्त आयोग (एन.के. सिंह समिति) ने राज्यों के बीच केंद्रीय करों के क्षैतिज हस्तांतरण (Horizontal Devolution) हेतु वैज्ञानिक मानकों का विन्यास किया। इसमें आय की दूरी को 45%, क्षेत्रफल को 15% और जन व पारिस्थितिकी को 10% का सांख्यिकीय भार दिया गया था।"

उपरोक्त राजकोषीय मानकों के आधार पर, 15वें वित्त आयोग द्वारा करों के क्षैतिज वितरण में 'जनसांख्यिकीय प्रदर्शन' (Demographic Performance) के मानक को कितना प्रतिशत भार आवंटित किया गया है?

- A) 2.5 प्रतिशत भार
- B) 12.5 प्रतिशत भार
- C) 15.0 प्रतिशत भार
- D) 7.5 प्रतिशत भार

प्रश्न 94: राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) के प्रभावी होने पर केंद्र और राज्यों के विधायी संबंधों में आने वाले सामरिक परिवर्तनों के संदर्भ में कौन सा प्रशासनिक विन्यास सत्य है?

- A) संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति केवल तभी प्राप्त करती है जब सभी राज्य विधानमंडल इसके लिए साझा संकल्प पारित करें।
- B) प्रांतीय विधानमंडलों की विधायी शक्तियां पूरी तरह समाप्त हो जाती हैं और राज्य सरकारें विधिक रूप से बर्खास्त कर दी जाती हैं।
- C) संसद द्वारा संकटकाल में राज्य सूची के विषयों पर निर्मित विधियां आपातकाल के दौरान राज्य के किसी पूर्व निर्मित कानून पर विधिक सर्वोच्चता रखती हैं।
- D) राष्ट्रपति को राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश (Ordinance) जारी करने की कोई विधायी शक्ति इस अवधि के दौरान प्राप्त नहीं होती है।

प्रश्न 95: मूल ढांचे के सिद्धांत (Basic Structure) के घटकों और उनसे संबद्ध ऐतिहासिक न्यायिक वादों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन I : इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण वाद (1975) में सर्वोच्च न्यायालय ने 'स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव' को संविधान के मूल ढांचे का एक अनिवार्य विनियामक स्तंभ घोषित किया था।

कथन II: मिनर्वा मिल्स वाद (1980) में न्यायपालिका ने यह विधिक सिद्धांत प्रतिपादित किया कि 'संसद की असीमित संशोधन शक्ति' स्वयं मूल ढांचे का हिस्सा है, जिसे सीमित नहीं किया जा सकता।

कथन III : एस.आर. बोम्मई वाद (1994) के अंतर्गत संघीय ढांचे, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र को संविधान के अभेद्य मूल ढांचे का अंग स्वीकार किया गया था।

निम्न में से कौनसा /कौनसे कथन सत्य है -

- A) केवल कथन I और II
- B) केवल कथन II और III
- C) केवल कथन I और III
- D) केवल कथन III

प्रश्न 96: अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग के संवैधानिक अधिदेश और उसकी अर्ध-न्यायिक प्रकृति के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथन और कारण पर विचार कीजिए:

कथन: वित्त आयोग एक संवैधानिक अर्ध-न्यायिक निकाय है जिसके अध्यक्ष और विशेष सदस्यों की विधिक नियुक्ति प्रत्येक पांच वर्ष में भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

कारण: वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली राजकोषीय सिफारिशें और राजस्व आवंटन के सिद्धांत केंद्र सरकार पर विधिक रूप से पूर्णतः बाध्यकारी (Binding) होते हैं।

- A) कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण, कथन की सही व्याख्या करता है
- B) कथन और कारण दोनों सत्य हैं परंतु कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं करता है
- C) कथन सत्य है परंतु कारण असत्य है
- D) कथन असत्य है परंतु कारण सत्य है

प्रश्न 97: राजकीय संघवाद के अंतर्गत सहायता अनुदान (Grants-in-aid) के संवैधानिक विन्यासों के संबंध में निम्नलिखित कूट कथनों और निष्कर्षों का मूल्यांकन कीजिए:

कथन: भारतीय संविधान में केंद्र द्वारा राज्यों को वित्तीय सुदृढ़ता प्रदान करने हेतु विधिक अनुदान (Statutory Grants) और विवेकाधीन अनुदान (Discretionary Grants) दोनों का स्पष्ट प्रावधान किया गया है।

निष्कर्ष I : अनुच्छेद 275 के तहत संसद द्वारा दिए जाने वाले विधिक अनुदान भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं और यह सहायता प्रत्येक राज्य के लिए भिन्न हो सकती है।

निष्कर्ष II : अनुच्छेद 282 के तहत प्राप्त विवेकाधीन अनुदान देने की वैधानिक शक्ति केवल केंद्र सरकार के पास है, राज्य विधानमंडलों को यह राजकोषीय अधिकार प्राप्त नहीं है।

- A) केवल निष्कर्ष I सत्य है
B) केवल निष्कर्ष II सत्य है
C) निष्कर्ष I और II दोनों असत्य हैं
D) निष्कर्ष I और II दोनों सत्य हैं

प्रश्न 98: वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद की विधिक कार्यप्रणाली और अप्रत्यक्ष करों के विनियामक क्षेत्रों को सुमेलित कीजिए:

सूची I :

- a) अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान होने वाली कर उगाही (IGST) का विनियामक आवंटन
b) किसी विशेष प्राकृतिक आपदा के दौरान अतिरिक्त संसाधन जुटाने हेतु करों की विशेष दरों का निर्धारण
c) जीएसटी परिषद की किसी आधिकारिक बैठक के संचालन हेतु कोरम (गणपूर्ति) की अनिवार्य सीमा
d) कर की दरों (Tax Slabs) के निर्धारण और विशिष्ट वस्तुओं को कर से छूट देने की सामान्य व्यवस्था

सूची II :

1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत परिषद की संप्रभु सिफारिशें
2. परिषद के कुल सदस्यों का न्यूनतम 50% सांख्यिकीय आयतन

3. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 269A का विशिष्ट विधिक संस्तर
4. जीएसटी परिषद के विनिर्दिष्ट विधिक प्रशासनिक कार्य

- A) a-3, b-1, c-4, d-2
B) a-3, b-1, c-2, d-4
C) a-1, b-3, c-2, d-4
D) a-4, b-2, c-1, d-3

प्रश्न 99: राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) की उद्घोषणा और उसके संसदीय अनुमोदन की विनियामक प्रक्रियाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असंगत है?

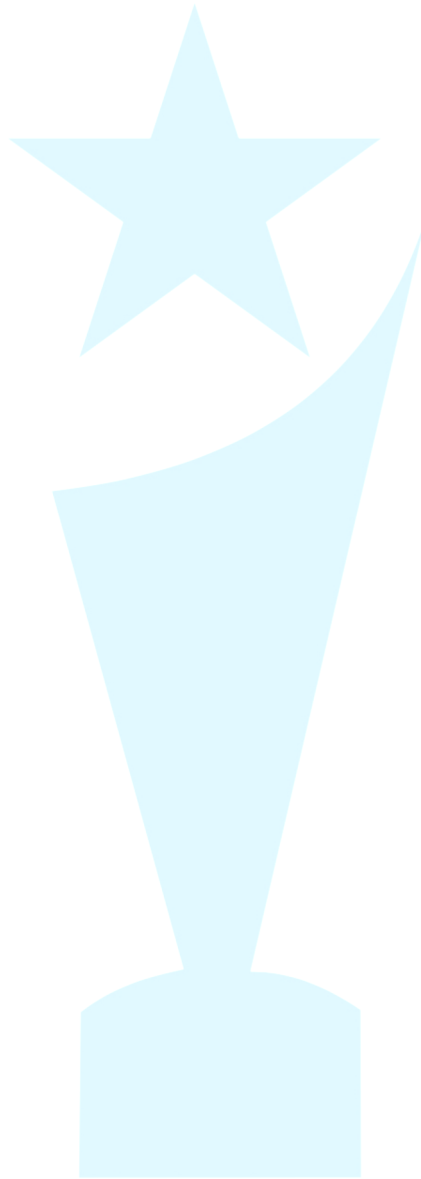
- A) राष्ट्रपति द्वारा की गई राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का संसद के दोनों सदनों द्वारा एक माह के भीतर विशेष बहुमत से अनुमोदन होना विधिक रूप से अनिवार्य है।
B) यदि आपातकाल की घोषणा के समय लोकसभा भंग हो, तो राज्यसभा के अनुमोदन के बाद नई लोकसभा की प्रथम बैठक से 30 दिन के भीतर इसका अनुमोदन आवश्यक है।
C) आपातकाल को अनिश्चित काल तक गतिक बनाए रखने हेतु प्रत्येक 1 वर्ष के अंतराल पर संसद के दोनों सदनों द्वारा पुनः संकल्प पारित करना अनिवार्य विन्यासित है।
D) राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को वापस लेने हेतु लोकसभा के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित संकल्प की आवश्यकता होती है।

प्रश्न 100: केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों और आधुनिक राजकोषीय संघवाद की विनियामक चुनौतियों के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान कीजिए:

- A) वर्तमान राजकोषीय विन्यास में केंद्र सरकार द्वारा अधिरोपित किए जाने वाले उपकर (Cess) और अधिभार (Surcharge) विभाज्य पूल (Divisible Pool) का अभिन्न हिस्सा होते हैं।
B) नीति आयोग के पास वर्तमान प्रशासनिक पारि-पारिस्थितिकी में राज्यों को वित्तीय अनुदान और बजटीय योजना कोष आवंटित करने की संप्रभु वैधानिक शक्ति निहित है।
C) जीएसटी परिषद में राज्यों के पास दो-तिहाई मत मूल्य होने के कारण वे केंद्र सरकार की पूर्ण असहमति के बावजूद भी स्वतंत्र रूप से कर दरें लागू कर सकते हैं।

D) 15वें वित्त आयोग ने क्षेत्रीय वितरण में
'जनसांख्यिकीय प्रदर्शन' मानक को शामिल कर

उन राज्यों को पुरस्कृत किया है जिन्होंने
जनसांख्यिकी नियंत्रण में सफलता पाई है।



wincompete